● वर्ष-5

● अंक-293

रायपुर, शनिवार
25 जुलाई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8>> वित्त मंत्री ने निःशुल्क पौधा ...

पेपर लीक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के कुछ ही घंटों बाद, शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने वाले एक ड्राफ्ट बिल (प्रारूप विधेयक) को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने बताया कि संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मौजूद कानूनों की तुलना में पेपर लीक में शामिल लोगों को अधिक सख्त सजा देने वाले ड्राफ्ट बिल को हरी झंडी दी गई। गुरुवार आधी रात के आसपास जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला एक विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।

यह घोषणा कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और मई में ह्श्वश्वञ्ज-त्त पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की जा रही है। इससे पहले आज कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के



इस्तीफ़े की उनकी मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पार्टी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ बातचीत का दूसरा दौर भी किया। जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने इस मांग पर जवाब देने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा सीजेपी के महीने भर से चल रहे विरोध प्रदर्शनों का मुख्य मुद्दा रहा है। 20 जुलाई को जब छात्रों ने संसद तक मार्च करने की कोशिश की, तो यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो वे विरोध प्रदर्शन को और तेज़ करेंगे।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगभग दो घंटे चली बैठक के बाद, सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार उनकी दो मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है। सीजेपी ने आत्महत्या करने वाले नीट उम्मीदवारों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवज़े और विरोध कर रहे छात्रों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने की मांग की है। रांका ने पत्रकारों से कहा सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। उन्होंने आगे कहा सरकार ने मुआवज़े और छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सीजेपी नेताओं और सरकार के बीच बैठक का तीसरा दौर शनिवार को होगा।

पेपर लीक पर क्या है कानून

देश में पहले ही से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू है। इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू है। सरकार नए संशोधन कर कानून को और सख्त और प्रभावशाली करने की तैयारी में है।

क्या है कानून में नियम

- देश में पेपर लीक से जुड़ा जो अधिनियम लागू है, उसमें यह प्रावधान हैं।
- पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल जेल और 10 लाख तक जुर्माना
- गिरोह शामिल होने पर 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना
- एजेंसी दोषी होने पर 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा की पूरी लागत वसूली और अगले 4 साल परीक्षा कराने पर बैन
- इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती है और समझौता नहीं हो सकता। जांच ष्ठस्क रैंक या उससे सीनियर अफसर करेंगे।

पेपर लीक विवाद- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसर बर्खास्त

नई दिल्ली. सरकार ने आज एनटीए पर बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। ये एनटीए पर सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि एनटीए का पूरा कायाकल्प किया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि परीक्षा व्यवस्था में क्या-क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं? आइए, पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं...

2026 नीट पेपर लीक विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। इसी बीच एनटीए ने 47 अफसरों को भी बर्खास्त कर दिया । सरकार की एनटीए पर ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए के अधिकारियों का कहना है कि एनटीए का पूरा कायाकल्प किया जाएगा और इसके बाद सुधारात्मक कदम लागू किए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि एजेंसी की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह कार्रवाई उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के पंचायती राज मंत्रालय में तबादले के एक दिन बाद सामने आई है संभावना है कि एनटीए के कामकाज में भी व्यापक बदलाव किए जा सकते हैं।

नीट पेपर लीक मामले में हटाए गए उच्च शिक्षा सचिव

नईदिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा सचिव के पद से हटा दिया है। उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, जबकि टी.के. अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विनीत जोशी 30 जून को संजय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च शिक्षा सचिव के साथ-साथ स्कूली शिक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे।

असम में बाढ़ से 50 लोगों की मौत 40 लोग अब भी लापता

गुवाहाटी । असम में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाकों तक राहत और बचाव दल अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कई लोगों के लापता होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिवसागर जिले के नजीरा अनुमंडल में करीब 40 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए अभियान जारी है। प्रशासन की टीमें प्रभावित और दुर्गम इलाकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।

सरमा ने कहा कि बाढ़ से बिजली का ढांचा क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित जिलों में 60 हजार से अधिक घर अब भी बिजली से वंचित हैं। सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों की करीब 20 फीसदी आबादी अब भी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। गंभीर स्थिति के कारण कई जलमग्न गांवों तक प्रशासनिक टीमें अभी नहीं पहुंच सकी हैं।



रायपुर। प्रदेश में मानसून की अच्छी वर्षा के साथ खेती-किसानी का कार्य गति पकड़ चुका है। इसी क्रम में दुर्ग शहर विधायक एवं प्रदेश के शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा विधि-विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव शुक्रवार को अपने गृहग्राम अहिवारा के समीप स्थित माटरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ खेत में उतरकर कृषि कार्यों में सहभागिता निभाई। मंत्री श्री यादव ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर धान रोपाई से पूर्व खेत की मताई की तथा लगभग दो एकड़ भूमि को रोपाई के लिए तैयार कराया।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मंत्रिपरिषद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली । केंद्रीय रेल राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार किया। हालांकि, इस्तीफे के पीछे की विस्तृत वजह आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में इस फैसले को



लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। वह पहले कांग्रेस में रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार में उन्हें रेल मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हाल के दिनों में पंजाब की राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका भी चर्चा में रही थी। रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में उनके स्थान पर किसे जिम्मेदारी सौंपते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक बदलावों से भी जुड़ा हो सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई अतिरिक्त आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

प्रमुख समाचार

अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक ने जारी किया वीडियो संदेश

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 26वें दिन गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे अपना अनशन समाप्त कर दिया। सोनम वांगचुक ने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लद्दाख की एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। इससे



पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। सांसदों और मंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि नीट पेपर लीक और देश की परीक्षा प्रणाली के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी। सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले दो दिनों से सरकार और उनके बीच बातचीत चल रही थी। वे सरकार से लिखित में आश्वासन चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें दो दिन अतिरिक्त अनशन पर बैठना पड़ा। आखिरकार, सरकार ने उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे दिया, जिसके बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का निर्णय लिया।

वांगचुक के अनशन खत्म होने पर मोदी का पहला रिएक्शन

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 26 दिनों से जारी अनशन को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे डॉक्टरों की सलाह मानने और जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुधारने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा मैं



सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से मिले आश्वासनों को पढ़कर सुनाया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले और 20 जुलाई 2026 के संसद मार्च में शामिल युवाओं पर पुलिस केस दर्ज न करने को लेकर सरकार सकारात्मक है। इसके अलावा संसद में पेपर लीक का स्थायी समाधान निकालने और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही, पेपर लीक की घटना की वजह से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

पेपर लीक मुद्दे पर खरगे का पीएम मोदी पर हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा- जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकतरफा मन की बात नहीं करनी होती।



खरगे की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के उस वीडियो संदेश के बाद आई है, जिसमें उन्होंने संसद में अगले हफ्ते पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने की बात कही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस प्रमुख ने कहा- प्रधानमंत्री जी संसद आने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा। उन्होंने मांग रखी कि सरकार पहले छात्रों से माफी मांगे और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। खरगे ने साफ किया कि इन कदमों के बाद ही विपक्ष शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।

राउत ने भूख हड़ताल खत्म करने के तरीके पर चिंता जताई

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के तरीके पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों और आम जनता की मौजूदगी में खत्म होनी चाहिए थी। राउत



ने वांगचुक के विरोध प्रदर्शन खत्म करने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन भूख हड़ताल खत्म कराने में केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका पर सवाल उठाए। राउत ने कहा कि 26 दिनों तक चले इस आंदोलन ने देश के युवाओं और आम नागरिकों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। जिस सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसी सरकार के दो मंत्री भूख हड़ताल खत्म होने के समय वहां मौजूद थे। इससे कई सवाल उठते हैं। उन्होंने आगे पूछा कि सरकार ने वांगचुक को क्या भरोसा दिलाया था और ज़ोर दिया कि इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस विरोध प्रदर्शन की मुख्य मांगों में से एक था, और राउत ने सवाल किया कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई।

सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर समय मांगा

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच बैठक पूरी हो गई है। बैठक के दौरान, सीजेपी ने पांच पैराग्राफ वाले ज्ञापन के ज़रिए अपनी मांगें लिखित रूप में सौंपीं। सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने किया, जबकि सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल



में सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल थे। सरकार के साथ बैठक के बाद, सीजेपी के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र उनकी दो मांगों को मानने के लिए तैयार हो गया है और यह भी कहा कि केंद्र शनिवार तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जवाब देगा। सीजेपी ने कहा कि सरकार उनकी दो मांगों को लेकर सकारात्मक दिखी। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने मुआवज़े (नीट की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों के लिए जिन्होंने आत्महत्या की) और छात्रों के खिलाफ़ एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

हरित ऊर्जा का महाकुंभ : निवेश, नवाचार और प्रेरणा का वैश्विक संगम

विनोद कुमार सिंह
तकियावाला

भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो2026 ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के नए युग का उद्घोष 2-5 नवम्बर, भारत मंडपम (नई दिल्ली) में जुटेगा विश्व स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, निवेश और नवाचार के भविष्य पर होगा वैश्विक मंथन

इक्कीसवीं सदी की वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार यदि कोई है तो वह ऊर्जा है। ऊर्जा अब केवल बिजली उत्पादन का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना बन चुकी है।यही कारण है कि आज पूरी दुनिया जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती, कार्बन उत्सर्जन में कमी की वैश्विक प्रतिबद्धताएँ और ऊर्जा सुरक्षा की नई आवश्यकताओं ने विश्व समुदाय को ऊर्जा संक्रमण (एनर्जी ट्रांजिशन) के ऐसे दौर में पहुँचा दिया है, जहाँ नवाचार ही भविष्य की दिशा तय करेगा। भारत ने भी इस परिवर्तन को समय रहते समझा और पिछले एक दशक में ऊर्जा क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, ऊर्जा भंडारण, विद्युत गतिशीलता तथा हरित परिवहन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों ने उसे विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है।आज भारत केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का सक्रिय भागीदार और भविष्य का नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 से 5 नवम्बर, 2026 तक आयोजित होने जा रहा भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो-2026 अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निवेश, नवाचार और प्रेरणा की थीम पर आधारित यह आयोजन केवल एक औद्योगिक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य का वैश्विक चिंतन-मंथन है। इसमें विभिन्न देशों के नीति-निर्माता, ऊर्जा मंत्री, वैज्ञानिक, उद्योगपति, निवेशक, स्टार्टअप, शोध संस्थान तथा अंतरराष्ट्रीय



संगठन एक मंच पर एकत्र होकर आने वाले दशकों की ऊर्जा दिशा पर विचार करेंगे। भारत के लिए यह सम्मेलन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक ओर यह देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा का परिचायक है, तो दूसरी ओर यह दुनिया को भारत की ऊर्जा क्षमता, निवेश संभावनाओं और तकनीकी नवाचार से परिचित कराने का सशक्त अवसर भी है।जिस प्रकार जी-20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत मंडपम वैश्विक कूटनीति का प्रतीक बना था, उसी प्रकार यह आयोजन भारत को हरित ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हो सकता है। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तथा संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएँ लगातार यह संकेत दे रही हैं कि आने वाले वर्षों में वैश्विक ऊर्जा निवेश का बड़ा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होगा।

इस परिवर्तन में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ विशाल ऊर्जा बाज़ार, अनुकूल नीतियाँ, युवा तकनीकी प्रतिभा, तीव्र औद्योगिक विकास और व्यापक निवेश संभावनाएँ उपलब्ध हैं।यही कारण है कि विश्व की अनेक अग्रणी ऊर्जा कंपनियाँ भारत को भविष्य के सबसे आकर्षक ऊर्जा निवेश गंतव्यों में शामिल कर रही हैं।आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। विकसित भारत-2047 का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है, जब देश की ऊर्जा व्यवस्था स्वच्छ, सुलभ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल तेल और गैस के आयात में कमी नहीं है, बल्कि ऐसी ऊर्जा व्यवस्था का निर्माण है जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ उद्योग, कृषि, परिवहन और आम नागरिक की आवश्यकताओं को भी समान रूप से पूरा कर सके। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार किया है। सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना, रूफटॉप सोलर कार्यक्रम, पवन ऊर्जा परियोजनाएँ, हरित हाइड्रोजन मिशन, बैटरी ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा तथा एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय रेलवे भी हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेल और हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा चुका है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। सम्मेलन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, बायो-एनर्जी, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी निर्माण, ग्रीन फाइनेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा भंडारण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित उद्यमों को भी अपनी तकनीकों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।

सूरजपुर में पथराव: गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों का हमला

डीएसपी 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए घायल



अंबिकापुर। सूरजपुर जिले में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को हिंसक हो गया। गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस घटना में डीएसपी राजेश जोशी समेत 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यह घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मदननगर-धरमपुर इलाके की है। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

बता दें कि प्रतापपुर क्षेत्र के मदननगर-धरमपुर इलाके में की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए। उनकी मांग है कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए। इसी मांग को लेकर इलाके में पहले से तनाव बना हुआ था। बीते दिनों एक टीम इलाके में सर्वे करने पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों ने टीम को बंधक बना लिया था। इसी घटना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया। प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने धरमपुर पहुंची। इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे।

देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए पथराव में डीएसपी राजेश जोशी समेत 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों के सिर और शरीर पर चोटें आईं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए सूरजपुर के साथ-साथ आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। मदननगर-धरमपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

एएसपी योगेश देवांगन के मुताबिक भूमि अधिग्रहण को लेकर हुए विवाद के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस बल पर पथराव किया। उनके अनुसार इसमें 24 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। इलाके में पुलिस बल तैनात है और मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है।

नीट पेपर लीक के विरोध में जगदलपुर में 2 युवाओं की भूख हड़ताल

एनएसयुआई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के कोतवाली चौक पर दो दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।



बस्तर। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जगदलपुर में भी विरोध तेज हो गया है। ह्स्ड्ढ और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के कोतवाली चौक पर दो दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

एनएसयूआई नेता लोकेश चौधरी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने दिल्ली पुलिस के द्वारा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया। 20 जुलाई को संसद मार्ग की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। उनका आरोप है कि बार-बार सामने आ रहे ह्श्वश्वञ्ज पेपर लीक के मामलों के बावजूद केंद्र सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। चौधरी ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग करें।

भूख हड़ताल के लिए सभी जिम्मेदारों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों को आवदेन दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने टेंट निकाल लिया। लेकिन बस्तर युवाओ के हौसले को नहीं झुका सकती है।

प्रदर्शनकारी अंकित सिंह ने आरोप लगाया कि धरना-प्रदर्शन के लिए प्रशासन से टेंट लगाने की अनुमति ली गई थी। लेकिन बाद में टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी गई इसके बावजूद ह्स्ड्ढ और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुले आसमान के नीचे ही अपना दो दिवसीय भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। यह आंदोलन छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर किया जा रहा है

मेडिकल स्टोर में एसडीएम की रेड कई अहम दस्तावेज जब्त



धमतरी। धमतरी जिले में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब(ईओडब्लू) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शहर के नया बस स्टैंड के पास स्थित अनिल मेडिकल पर अचानक दबिश दी। इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों और मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला साल 2004 का है। छत्तीसगढ़ में लोक कला जत्था योजनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन के नाम पर करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था। जांच के दौरान इस प्रकरण में अनिल मेडिकल की संलिप्तता और वित्तीय लेन देन की बात सामने आई थी, जिसके आधार पर ईओडब्लू की टीम ने आज छापेमार कार्रवाई की है। ईओडब्लू की टीम ने रणनीति के तहत तड़के सुबह ही अनिल मेडिकल स्टोर में पहुंचकर छापा मारा। टीम ने दुकान को अपने कब्जे में लेकर घंटों तक दस्तावेजों की सघन जांच की और दुकान के संचालकों से पूछताछ की। घंटों चली इस कार्रवाई के बाद ईओडब्लू की टीम अपने साथ कई महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज लेकर रवाना हुई है।

छत्तीसगढ़ के भांचा श्रीराम की आस्था के सम्मान में बिलासपुर में निकलेगी 3 दिवसीय श्रीराम श्रद्धा यात्रा



बिलासपुर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के भांचा श्रीराम की आस्था के सम्मान में तीन दिवसीय श्रीराम श्रद्धा यात्रा निकाली जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा में भांचा और ननिहाल का रिश्ता केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि स्नेह, सम्मान, आस्था और आत्मीयता का प्रतीक है। लोकमान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं। ऐसे में अयोध्या धाम स्थित रामलला के दरबार से जुड़ी चोरी की घटना ने प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर के करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं को गहराई से आहत किया है। अनेक श्रद्धालुओं ने इसे अपने भांचा श्रीराम के सम्मान और आस्था पर लगी चोट के रूप में महसूस किया। इन्हीं श्रद्धाभावों को सम्मान देने और छत्तीसगढ़ के ननिहाल की ओर से अपने भांचा श्रीराम के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण व्यक्त करने के उद्देश्य से 25 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक तीन दिवसीय श्रीराम श्रद्धा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित श्रद्धा के नारियल एकत्र किए जाएंगे। इन नारियलों को अयोध्या धाम ले जाकर रामलला के श्रीचरणों में समर्पित किया जाएगा। यह केवल नारियल का समर्पण नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के ननिहाल की ओर से अपने भांचा श्रीराम के प्रति अटूट श्रद्धा, स्नेह, आशीर्वाद और समर्पण का भावपूर्ण संदेश होगा। 25 जुलाई को दोपहर 12ः00 बजे देवकीनंदन चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर, तिलक नगर में वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना एवं श्रीराम वंदना के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर मंगला क्षेत्र से आने वाला श्रद्धालुओं का विशेष जत्था भी यात्रा में शामिल होगा। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व श्रद्धालु घर-घर जाकर पीले चावल (अक्षत) एवं सुपारी भेंट कर लोगों को इस पुण्य यात्रा में शामिल होने का आत्मीय निमंत्रण देंगे। यात्रा की जानकारी देते हुए बेलतरा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे विजय केशरवानी ने कहा कि यह यात्रा पूर्णत: श्रद्धामयी, शांतिपूर्ण एवं गैर-राजनीतिक होगी। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का विरोध या प्रदर्शन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप अपने भांचा श्रीराम के प्रति अटूट श्रद्धा, सम्मान और समर्पण को पूरे गौरव एवं गरिमा के साथ अयोध्या धाम तक पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि यात्रा के प्रत्येक दिवस की पदयात्रा के समापन पर भगवान श्रीराम को भोग अर्पित किया जाएगा और समस्त श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद (भंडारा) का आयोजन किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में यात्रा में शामिल होकर पदयात्रा, भोग एवं महाप्रसाद का पुण्य लाभ प्राप्त करें। उन्होंने समस्त रामभक्तों, मातृशक्ति, युवाओं एवं सर्वसमाज से भावपूर्ण अपील करते हुए कहा कि वे इस ऐतिहासिक एवं पावन यात्रा में सहभागी बनें तथा श्रद्धा का एक नारियल अर्पित कर छत्तीसगढ़ के ननिहाल की ओर से अपने भांचा श्रीराम के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का संदेश रामलला के श्रीचरणों तक पहुँचाने के इस पुण्य संकल्प में सहभागी बनें।

जेल में ही सजा शादी का मंडप



जिस युवक को परिजनों ने भेजा था सलाखों के पीछे, अब उसी से युवती ने रचाया विवाह

जगदलपुर। बस्तर जिले के जगदलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय जेल में सजा काट रहा एक कैदी दूल्हा बन गया है। जिस युवती के परिजनों ने उसे 376 के मामले में अंदर करवाया था अब वह उससे ही शादी करने जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, राजूर गांव निवासी सुरेश सेठिया और मनमती कश्यप एक-दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि, दोनों के अलग-अलग जातियों से होने के कारण युवती के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। विरोध इस हद तक बढ़ा कि लड़की के घरवालों ने सुरेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले में धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

युवक के जेल जाने के बाद कहानी में एक मया मोड़ आया। अपने प्यार को सलाखों के पीछे देख युवती चुप नहीं बैठी और उसने खुद अदालत का रुख किया। उसने कोर्ट को बताया कि दोनों अपनी मर्जी से एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। युवती की बात सुनने के बाद अदालत ने पुलिस और जेल प्रशासन को दोनों की शादी कराने के निर्देश दिए।

आदेश मिलते ही जेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दीं। जेल परिसर में पहली बार शादी का मंडप सजा। दोनों ने सलाखों के बीच सात फेरे लिए और कानून की निगरानी में दो प्रेमी जीवनभर के बंधन में बंध गए। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब सच सामने आता है तो कानून भी न्याय के साथ संवेदनशीलता का रास्ता अपनाता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जांजगीर में देव शयन से पहले 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह

जांजगीर-चांपा। जिले के नगर पालिका सामुदायिक भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का भव्य आयोजन किया गया। यह विवाह हिंदू रीति-रिवाज के साथ पूरी तरह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। मानसून की बारिश को देखते हुए नव-दम्पत्तियों की सुविधा के लिए खुले मैदान के बजाय सामुदायिक भवन में सुरक्षित व्यवस्था की गई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की मौसी के घर से वापसी और देवशयनी एकादशी से ठीक पहले इस शुभ मुहूर्त को चुना गया था, क्योंकि एकादशी के बाद चार महीनों के लिए सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस गरिमामयी समारोह में जांजगीर, नवागढ़ और अकलतरा विकासखंड के कुल 11 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रेखा गढेवाल और जिला पंचायत सदस्यों ने शामिल होकर नव-दम्पत्तियों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें अंतर-जिला जुड़ाव भी देखने को मिला।

शिक्षकों की कमी से नाराज पालकों ने स्कूल में जड़ा ताला

कोंडागांव। जिले के पीएमश्री स्कूल डीपोपारा में शिक्षकों की कमी से नाराज पालकों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। पालकों का कहना है कि शिक्षकों की नियमित भर्ती और व्यवस्था सुधारने के लिए कई बार आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसके चलते अब प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा है। पालकों के अनुसार, पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए केवल दो शिक्षक पदस्थ हैं। इनमें से एक शिक्षिका हिना कश्यप स्वास्थ्य कारणों से लंबे समय से नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रही है। ऐसे में पूरे स्कूल की पढ़ाई का जिम्मा एक ही शिक्षिका पर होने से बच्चों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे पालकों ने कहा कि जब जिला मुख्यालय स्थित पीएमश्री स्कूल की यह स्थिति है तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं की जाती और पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

सेवा भूमि पर कोटवार नहीं कर सकते मालिकाना हक का दावा

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कोटवारों और उसके उत्तराधिकारियों की सेवा भूमि पर मालिकाना हक के एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाया है। चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की फुल बेंच ने कहा कि 1950 में जमींदारी उन्मूलन से पूर्व मालगुजारों या जमींदारों द्वारा कोटवारों को सेवा के बदले दी गई जमीन पर कोटवार या उनके वारिस भू स्वामी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। बता दें, कि दो डिवीजन बेंच के ऑर्डर में विरोधाभास के बाद सिंगल बेंच ने मामला पूर्ण पीठ (फुल बेंच) को रेफर किया था। दरअसल, कबीरधाम जिले के गजेंद्र दास और स्थानीय जरहाटोला निवासी सुकृत दास ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर पूर्व में हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देकर सेवा भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने पाया कि दो अलग अलग डिवीजन बेंचों के निर्णय में परस्पर विरोधाभास है। इसी विरोधाभास को देखते हुए मामले को फुल बेंच के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां कोटवारों के विरुद्ध हाईकोर्ट का निर्णय सामने आया है।

प्रयास आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाओं का अंबार

जगदलपुर। जगदलपुर के धुरगुड़ा स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने खुलकर आवाज उठाई। छात्रों का आरोप है कि जिस समय उनकी कक्षाएं चलती हैं, उसी दौरान परिसर में निर्माण कार्य कराया जाता है, जिससे मशीनों का शोर पढ़ाई में लगातार बाधा बन रहा है। बच्चों का कहना है कि आईआईटी-जेईई और नीट की तैयारी कराने वाले अनुभवी शिक्षकों को अचानक हटा दिया गया, जबकि उनकी जगह योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। विरोध करने पर उनकी बात सुनने के बजाय टाल दिया जाता है और कथित तौर पर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो जैसी बातें कही जाती हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार शिक्षकों को बदला जाता है, जिससे उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। कई छात्रों ने दावा किया कि विरोध करने पर टीसी काटने, नोटिस देने और एफआईआर की धमकी तक दी गई। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, छात्रों ने हॉस्टल की बदहाल व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए।

राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही: महंत दंपति

जांजगीर चांपा। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बिसाहु दास महंत नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के पिता है. जांजगीर चांपा में उनकी 48 पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने चरणदास महंत और बहू और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने बिसाहु दास महंत की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बिलासपुर से आए नन्हे कलाकार तनिष्क वर्मा ने कबीर भजन भी पेश किया। बिसाहु दास महंत अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज और प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे। वे 1952 से 1977 तक लगातार 6 बार विधायक रहे। वे मध्यप्रदेश में कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री भी रहे। उन्हें छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विकास का स्वप्नदृष्टा और %बांगो बांध परियोजना% का शिल्पकार भी माना जाता है। पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं।

बीपीसीएल गैस पाइपलाइन विस्तार के दौरान सड़क हादसा

बीपीसीएल गैस पाइपलाइन विस्तार के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि दी गई है.

मृतक के पत्नी को कंपनी ने दी आर्थिक सहायता

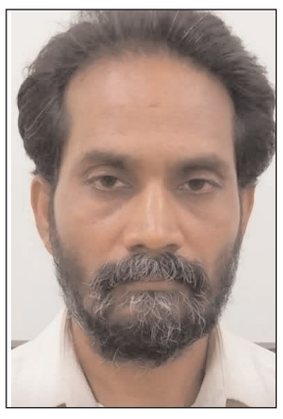


मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। बीपीसीएल गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले राघवेंद्र दोषी के परिजनों को कंपनी ने आर्थिक सहायता दी है। जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रवासियों के संयुक्त प्रयास के बाद बीपीसीएल कंपनी ने मृतक की पत्नी को सवा दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एनएच-43 पर बीपीसीएल की गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना का कार्य चल रहा था। इसी दौरान निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन की चपेट में आने से स्कूटी सवार 24 वर्षीय राघवेंद्र घोषी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था। स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में सिटी कोतवाली के सामने शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने मृतक परिवार को उचित मुआवजा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही की जांच की मांग की थी।

घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और बीपीसीएल कंपनी के अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों के लगातार दबाव बनाए जाने और प्रशासन की मध्यस्थता के बाद कंपनी ने मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई। सहायता राशि मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन समेत समस्त शहरवासियों का आभार जताया।

जिला अस्पताल प्रभारी रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा

सक्ती जिला अस्पताल प्रभारी सिविल सर्जन संतोष पटेल रिश्वत लेते एसीबी में ट्रैप हुए हैं.संतोष पटेल ने पे डाटा बनाने के लिए पैसे मांगे थे.



सक्ती। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को एसीबी ने रिश्वत लेते ट्रैप किया है। सिविल सर्जन संतोष पटेल ने फॉर्मासिस्ट का पे डाटा बनाने के एवज में एक लाख रुपए की मांग की थी। जिसकी शिकायत एसीबी से की गई थी।इसके बाद एसीबी ने ट्रैप बनाकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जिला अस्पताल सक्ती में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर गंगा प्रसाद रत्नाकर करते हैं। जो फरवरी 2026 से जिला अस्पताल सक्ती में अटैचमेंट के तहत सेवाएं दे रहे हैं।

लेकिन जिला अस्पताल सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन संतोष कुमार पटेल ने फरवरी से लेकर जून 2026 तक का पे डाटा बनाकर सीएमएचओ कार्यालय नहीं भेजा।

इसके एवज में गंगा प्रसाद से फरवरी से जून तक पे डाटा भेजने के लिए रिश्वत की मांग की गई। गंगा प्रसाद के मुताबिक पांच महीने का पे डाटा बनाने के लिए 1 लाख रुपए मांगें गए। गंगा प्रसाद सिविल सर्जन को पैसा ना देकर उसे एसीबी के हाथों पकड़वाना चाहता था,लिहाजा उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन में कर दी।

शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी यूनिट बिलासपुर ने ट्रैप की योजना बनाई। गुरुवार को टीम ट्रैप के लिए रवाना हुई। आरोपी संतोष कुमार पटेल ने प्रार्थी को रिश्वत की रकम लेकर अपने अस्थायी निवास डभरा बुलाया था।

इसके बाद प्रार्थी एसीबी की टीम के साथ डभरा पहुंचा। इसके बाद आरोपी संतोष पटेल अपनी गाड़ी में डभरा कॉलेज मोड़ के पास पहुंचा और प्रार्थी को गाड़ी के अंदर बिठाकर रिश्वत की रकम ली।जैसे ही आरोपी ने पैसे लिए एसीबी की टीम ने त्वरित एक्शन लेते हुए उसे रंगे हाथ दबोच लिया।

रिश्वत की रकम 1 लाख रुपए को संतोष पटेल के पास से बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से शुक्रवार



को यहां लोकभवन में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रावधानों पर राज्यपाल से विचार-विमर्श किया। श्री डेका ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार के सबंद्ध में अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई दुर्ग के कुलाधिपति श्री आईपी मिश्रा, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलाधिपति श्री सुशील चंद्राकर, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति डॉ. संदीप अरोड़ा, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गरियाबंद और रायपुर के कुलपति डॉ. आनंद महलवार, अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति श्री अभिषेक अग्रवाल, दावड़ा विश्वविद्यालय रायपुर के सीईओ श्री चिन्मय दावड़ा, कोलंबिया विश्वविद्यालय रायपुर के प्रो. कुलाधिपति श्री हरजीत सिंह हूरा उपस्थित थे।

शीतकालीन सत्र में पारित होगा समान नागरिक संहिता - सीएम साय

रायपुर। कर्नाटक रवाना होने से पहले मीडिया



से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेसी कश्मीर की तरह पत्थरबाजी में उतर आए हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन कश्मीर में जैसे पत्थरबाजी होती है, कांग्रेसी भी वैसे ही पत्थरबाजी में उतर आए हैं। कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे पारित किया जाएगा।

वित्त मंत्री चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय दल को दी शुभकामनाएं

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अनुशासन, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर विश्व खेल जगत में देश की पहचान को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय दल खेल भावना, उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पण के साथ विश्व पटल पर तिरंगे का गौरव बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की जीत के साथ-साथ उनका संघर्ष, परिश्रम और राष्ट्र के लिए समर्पण भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देशवासियों की शुभकामनाएं और विश्वास पूरे भारतीय दल के साथ हैं। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने सभी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना करते हुए कहा कि पूरा देश उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश का मान और गौरव बढ़ाएंगे।

आमानाका फ्लाईओवर पर कार ने लोगों को लिया चपेट में, कई घायल

रायपुर। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत



आने वाले अमानाका फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों पहुंचाया अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार एक महिला चला रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार ने फ्लाईओवर पर चल रहे दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सरस्वती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

भूपेश की धमकी भरी भाषा हताशा और राजनीतिक बौखलाहट का प्रमाण : कश्यप

पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को खुली चेतावनी देना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का घोर उल्लंघन

रायपुर। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों एवं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को लेकर दिए गए कथनों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह भाषा किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की नहीं, बल्कि राजनीतिक हताशा और मानसिक असंतुलन की स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन कानून के रक्षकों और संवैधानिक व्यवस्था को खुलेआम धमकाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का यह कहना कि पुलिस अधिकारी ध्यान रखें, भाजपा कुछ ही महीनों की मेहमान है... फिर मिलेंगे न केवल पुलिस प्रशासन को डराने का प्रयास है, बल्कि यह कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की खुली कोशिश भी है। यह बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और कांग्रेस की उस मानसिकता को उजागर करता है, जिसमें सत्ता को ही कानून से ऊपर माना जाता रहा है। कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब भय, दबाव और राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति से बाहर निकल चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, जहाँ पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ अपना दायित्व निभा रही है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को भविष्य की राजनीतिक धमकियाँ देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अपराध, भ्रष्टाचार और सत्ता संरक्षण की घटनाओं ने जनता का



विश्वास तोड़ा, जिसका परिणाम कांग्रेस को चुनाव में पराजय के रूप में मिला। जनता ने भ्रष्टाचार, अहंकार और कुशासन को नकारते हुए भाजपा को जनादेश दिया है। अब जनता के इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक निराशा व्यक्त कर रहे हैं। जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कानून हाथ में लेने, प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाता है और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है, तब कांग्रेस के नेता पुलिस पर ही दबाव बनाने लगते हैं। यह प्रवृत्ति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस आज भी कानून के शासन में नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव की संस्कृति में विश्वास रखती है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विपक्ष का दायित्व व्यवस्था को मजबूत करना है, न कि पुलिस प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना। पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी भाषा और आचरण की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन धमकी, भय और दबाव की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार स्पष्ट रूप से कानून के शासन में विश्वास रखती है। प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी दल या पद से जुड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। पुलिस अपना कार्य पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप करती रहेगी और सरकार हति में कानून के साथ खड़ी रहेगी।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जनता कांग्रेस की धमकी, डर और अराजकता की राजनीति को पहले ही नकार चुकी है। अब समय आत्ममंथन का है, न कि पुलिस प्रशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को धमकाने का। छत्तीसगढ़ की जनता सुशासन, शांति और कानून के राज के साथ है तथा किसी भी प्रकार की राजनीतिक गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करेगी।

मोदी के निर्णायक कदम और वांगचुक के अनशन समाप्त होने से विपक्ष का भारत विरोधी एजेंडा बेनकाब : देव

■ **विपक्ष का मकसद समाधान नहीं, बल्कि देश में भ्रम और अराजकता फैलाना था**

रायपुर। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई ऐतिहासिक एवं कड़े कदमों की घोषणा तथा अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक द्वारा अनशन समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस सहित इण्डी गठबंधन के घटक दलों पर तीखा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इन घटनाक्रमों ने विपक्ष के असली राजनीतिक चरित्र और उनके भारत विरोधी एजेंडे की पूरी तरह पोल खोल दी है।

देव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए त्वरित और अभूतपूर्व कदम उठाने की घोषणा की है। श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा न केवल



त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश दिए हैं, बल्कि दोषियों को 5 से 10 साल की कड़ी सजा, कठोर जमानत शर्तों और दोषी पाए जाने पर संबंधित कोचिंग संस्थानों को बंद करने जैसे कठोर प्रावधानों वाले कानून का मसौदा तैयार करवाया जा रहा है। सरकार की इस त्वरित संवेदनशीलता और पारदर्शी नीयत के बाद केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने भी सरकार के सकारात्मक रुख पर भरोसा जताते हुए अपना अनशन समाप्त कर दिया। श्री देव ने कहा कि यह पूरी घटना यह दर्शाती है कि मोदी-सरकार देश के छात्रों और युवाओं के हित में चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन दूसरी ओर, कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एकमात्र एजेंडा छात्रों के कंधे पर बन्दूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकना और देश में असंतोष की आग भड़काना था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को कभी भी छात्रों के भविष्य या न्याय से कोई लेना-देना नहीं था। वे केवल देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते थे। जब सरकार ने समस्या के जड़ से समाधान के लिए कड़ा कानून बनाने की दिशा में काम किया, तो इण्डी गठबंधन का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया। श्री देव ने कहा कि देश के युवा समझदार हैं और वे देख सकते हैं कि कौन उनके भविष्य के लिए काम कर रहा है और कौन उनके नाम पर राजनीति कर रहा है? भाजपा सरकार देश के हर होनहार छात्र के हक की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

महानदी जल विवाद के समाधान हेतु केंद्र की मध्यस्थता का फैसला ऐतिहासिक व स्वागतयोग्य : भाजपा

■ **प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद रूपकुमारी चौधरी ने जताया भरोसा**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के मध्य वर्षों से चले आ रहे महानदी जल विवाद को केंद्र सरकार की मध्यस्थता से सुलझाने की दिशा में बनी सहमति का पुरजोर स्वागत किया है। श्रीमती चौधरी ने इस ऐतिहासिक पहल को दोनों राज्यों के विकास और किसानों के हित में एक बड़ा व दूरगामी कदम बताया है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल में लम्बे समय से लम्बित इस गम्भीर मामले में केन्द्र सरकार की



मध्यस्थता स्वीकार करने पर दोनों राज्यों, ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ ने जो सहमति जताई है, उससे आपसी सद्भाव और संवाद के जरिए स्थायी समाधान की उम्मीदें बेहद मजबूत हुई हैं। श्रीमती चौधरी ने केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि श्री साहू द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मिलकर की गई सार्थक चर्चा और केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित करने के अनुरोध का ही परिणाम है कि आज यह ऐतिहासिक मोड़ सम्भव हो सका है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के बीच जल्द ही आयोजित होने वाली उच्चस्तरीय बैठक से जल बँटवारे से जुड़े विवादित मुद्दों पर आपसी सहमति कायम होगी। ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बेला एस. त्रिवेदी के समक्ष दोनों राज्यों द्वारा केंद्र की मध्यस्थता पर जताई गई रजामंदी यह दर्शाती है कि लम्बी प्रक्रियाओं की तुलना में आपसी बातचीत से मसले सुलझाना अधिक प्रभावी है। श्रीमती चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों राज्यों की डबल इंजन सरकारें और केंद्र सरकार का मार्गदर्शन महानदी विवाद का ऐसा सर्वमान्य व न्यायसंगत समाधान निकालेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओड़िशा के जन-जन का हित सुरक्षित होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने उद्योगों के साथ बनाई दीर्घकालिक सहयोग की रणनीति

■ **आप सबके सहयोग से हम स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाएंगे : प्रमुख सचिव निगार**

रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से राज्य में पोषण, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी उद्देश्य से आज सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में विभाग और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालिक सहयोग की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शासन द्वारा संचालित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में उद्योगों की सामाजिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीएसआर सहयोग के माध्यम से पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण तथा नवाचार आधारित गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने उद्योगों से विभाग के साथ दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा, आप



सबके सहयोग से हम स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाएंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग तीन प्रमुख आयामों—महिला सशक्तिकरण, बच्चों का संरक्षण तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण—पर निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि सीएसआर सहयोग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री, डिजिटल संसाधन, पोषण संवर्धन, स्वच्छ पेयजल, खेल सामग्री, स्वच्छता सुविधाएं तथा नवाचार आधारित गतिविधियों का विस्तार किया जा सकता है।

बैठक में विभाग द्वारा तैयार की गई संभावित सीएसआर परियोजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। इसमें कुपोषण उन्मूलन, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन, पोषण वाटिका एवं मुनगा पौधारोपण, प्रारंभिक बाल विकास गतिविधियां, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई। बैठक के दौरान उद्योगों के प्रतिनिधियों ने विभाग के प्रस्तावों में रुचि व्यक्त करते हुए विभिन्न योजनाओं में सहयोग की संभावनाओं पर अपने सुझाव साझा किए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

■ **कार्यपालन अभियंताओं, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश**

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीडब्लूडी मुख्यालय 'निर्माण भवन' में आज आयोजित बैठक में जिलों के कार्यपालन अभियंताओं, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी बैठक में शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न संभागों के कार्यपालन अभियंता, ठेकेदार और जेल अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में जुड़े।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में प्रदेश की विभिन्न जेलों में



निर्माणाधीन बैरकों, बाउंड्रीवॉल्स, शौचालयों और वॉच टॉवर्स के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ ही सभी जेलों के अधीक्षकों से निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थलों का नियमित दौरा कर कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को भी निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा।

श्री बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और जेल अधीक्षकों को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए जेल परिसर के भीतर निर्माण सामग्रियों के परिवहन की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने जेल अधीक्षकों को श्रमिकों को रोज काम के लिए पर्याप्त समय देने को कहा। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता ने बैठक में कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं। नए बैरकों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार से राहत मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मैदानी अधिकारियों, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को तेज गति से काम कर कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में रायपुर केन्द्रीय जेल में पार्किंग शेड, पाठशाला शेड, मुलाकातियों-परिजनों के लिए शेड व शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बिलासपुर के नगोई में 1500 आवास क्षमता के विशेष जेल, जिला जेल धमतरी और गरियाबंद में बाउंड्रीवॉल, जिला जेल जांजगीर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कांकेर, संजारी-बालोद तथा उप जेल सारंगढ़ में बैरक निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की।

राजीव भवन घेराव मामला : थाने में लिखित आश्वासन के बाद कांग्रेस का धरना खत्म

■ **भाजपा नेताओं पर एफआईआर की है मांग, पुलिस से तीन मांगों पर बनी सहमति**

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन घेराव को लेकर छिड़ा सियासी विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और खम्हारडीह थाने के घेराव के बाद पुलिस और कांग्रेस के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है।पुलिस ने कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धरना-प्रदर्शन को फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यदि तय समयसीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा।

राजधानी रायपुर का खम्हारडीह थाना गुरुवार से कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाने पहुंचे और पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना था कि राजीव भवन की घटना में केवल कांग्रेस



नेताओं पर कार्रवाई की गई, जबकि बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया।

कांग्रेस ने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, मंत्री ओ।पी। चौधरी, विधायक पुरंदर मिश्रा, भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिहा सहित अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि राजीव भवन घेराव के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं में इन नेताओं की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस के अनुसार 22 जुलाई को बीजेपी और भाजयुमो कार्यकर्ता राजीव भवन के सामने पहुंचे, जहां अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।इसके बाद पत्थर, पानी की बोतलें, पाउच, चप्पल और अन्य सामान फेंके गए, जिससे कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए।पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की और राजीव भवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया।

कांग्रेस ने अपने आवेदन में दावा किया कि पूरी घटना शंकर नगर चौक के सीसीटीवी कैमरों और मीडिया कैमरों में रिकॉर्ड हुई है।पार्टी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर काउंटर एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

करीब एक रात तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस और कांग्रेस के बीच बातचीत हुई। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस की तीनों प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन दिया, जिसके आधार पर धरना समाप्त कर दिया गया।

पहली सहमति - कांग्रेस के आवेदन पर सात दिनों के भीतर जांच पूरी कर राजीव भवन पर हमला करने के आरोपी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

दूसरी सहमति - घायल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेडिकल परीक्षण (डॉक्टरी मुलाहिजा) कराया जाएगा। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

तीसरी सहमति - जिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं, उनकी विवेचना कर यदि आवश्यक हुआ तो उन धाराओं को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

पुलिस से लिखित आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

दीपक बैज ने कहा कांग्रेस पुलिस को कार्रवाई के लिए सात दिन का समय दे रही है। यदि तय समयसीमा में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी फिर से आंदोलन शुरू करेगी

राजीव भवन विवाद अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई का भी रूप ले चुका है।एक ओर कांग्रेस समान और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं पुलिस जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दे रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सात दिनों के भीतर पुलिस जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचती है । बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। इसी पर आगे की राजनीतिक रणनीति और आंदोलन की दिशा तय होगी।

अब आगे क्या? इस्तीफा या पेपर लीक पर संसद में बहस?

सौरभ वार्ष्णेय

देश की संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा, जवाबदेही और समाधान की अपेक्षा की जाती है। लेकिन मानसून सत्र के शुरुआती तीन दिन जिस प्रकार लगातार हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़े हैं, उसने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या संसद जनहित के मुद्दों के समाधान का मंच बनेगी या केवल राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बनकर रह जाएगी? वर्तमान गतिरोध का सबसे बड़ा कारण देशभर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक की घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य, उनकी वर्षों की मेहनत और पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का विषय मानते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग पर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मंत्री का इस्तीफ़ा केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी तय होने और नैतिक उत्तरदायित्व के आधार पर होना चाहिए। वहीं विपक्ष का यह तर्क भी पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता कि जब सरकार उपलब्धियों का श्रेय स्वयं लेती है, तो गंभीर प्रशासनिक विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी भी उसे स्वीकार करनी चाहिए। यही कारण है कि इस्तीफ़े की मांग राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि संसद में इस पूरे प्रकरण पर गंभीर, तथ्यात्मक और व्यापक चर्चा हो। केवल नारेबाज़ी या सदन को बाधित करने से न तो छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और न ही परीक्षा प्रणाली में सुधार आएगा। देश यह जानना चाहता है कि आखिर बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां है? कौन-से संगठित गिरोह इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं? अब तक कितनों पर कार्रवाई हुई? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ठोस रणनीति क्या है? संसद में यदि इन सभी प्रश्नों पर विस्तृत बहस होती है तो यह लोकतंत्र और छात्रों—दोनों के हित में होगा। बहस से जवाबदेही भी तय होगी और सुधार की दिशा भी स्पष्ट होगी। लेकिन यदि बहस से पहले केवल इस्तीफ़े की मांग और सरकार की ओर से केवल राजनीतिक प्रतिरोध चलता रहा, तो सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों युवाओं का होगा, जिनका भविष्य इस पूरे विवाद के बीच अधर में लटका हुआ है। इस बीच राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार व्यापक होता दिखाई दे रहा है। विभिन्न राज्यों से छात्र वहां पहुंच रहे हैं और निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। कुछ समय पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद यह माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शनों की धार कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन वर्तमान छात्र आंदोलन यह संकेत देता है कि युवाओं का आक्रोश केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के प्रति गहराते अविश्वास का प्रतीक बन चुका है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह पेपर लीक पर संसद में चर्चा करने और आंदोलनरत छात्रों से संवाद के लिए भी तैयार है। यदि ऐसा है, तो यह स्वागतयोग्य पहल हो सकती है। लोकतंत्र में संवाद ही किसी भी संकट का सबसे प्रभावी समाधान माना जाता है। लेकिन संवाद तभी सार्थक होगा जब उसके साथ ठोस निर्णय, समयबद्ध कार्रवाई और पारदर्शिता भी जुड़ी हो।

संवाद से ही सुलझेगा युवा असंतोष

योगेश कुमार गोयल



18 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ, उसने लोकतंत्र के चेहरे पर कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर शांतिपूर्ण, संवैधानिक और नैतिक विरोध के प्रतीक के तौर पर वैज्ञानिक, नवाचारकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति का वह रूप सामने आया, जिसने संवाद की जगह बल प्रयोग को प्राथमिकता दी। जिस तरह से उन्हें सफेद चादर में लपेटकर पुलिस द्वारा जबरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया, वह दृश्य केवल एक व्यक्ति के साथ हुई कार्रवाई नहीं थी बल्कि उस पूरी सोच का प्रतीक था, जिसमें असहमति को समस्या मान लिया गया है। सरकार का यह अनुमान कि वांगचुक को हटाने के बाद आंदोलन स्वत: समाप्त हो जाएगा, एक गंभीर राजनीतिक भूल साबित हुआ। इसके विपरीत, इस कार्रवाई ने युवाओं के भीतर दबी हुई असंतोष की आग को हवा दे दी। यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि उस गहरे अविश्वास का परिणाम थी, जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मुद्दों पर लगातार पनपता रहा है। जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन को इस तरह कुचलने का प्रयास किया जाता है तो यह संदेश जाता है कि सरकार संवाद के बजाय दमन को अधिक प्रभावी मानती है।

लोकतंत्र का मूल तत्व यह है कि नागरिकों को अपनी बात कहने, विरोध करने और अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष करने का अधिकार हो। यह अधिकार केवल संविधान की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उसका सम्मान व्यवहार में भी होना चाहिए। जब तक कोई आंदोलन हिंसक नहीं होता, तब तक उसे दबाने के बजाय समझने और समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जंतर-मंतर की घटना ने यह संकेत दिया कि सरकार इस बुनियादी सिद्धांत से दूर होती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू युवाओं की प्रतिक्रिया है। आज का युवा केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सूचनाओं और जागरूकता से संचालित होता है। वह हर घटना को देखता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर अपनी प्रतिक्रिया देता है। सोनम वांगचुक के साथ हुई घटना ने युवाओं को महसूस कराया कि उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि 'चलो संसद' के आह्वान को अभूतपूर्व समर्थन मिला।

यहां यह समझना भी जरूरी है कि यह आक्रोश केवल एक घटना का परिणाम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बार-बार पेपर लीक, परीक्षाओं में अनियमितताएं और परिणामों में कथित धांधली ने छात्रों के भविष्य को अस्थिर कर दिया है। नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा, जिस पर लाखों छात्रों का करियर निर्भर करता है, उसमें भी पारदर्शिता पर सवाल उठना बेहद गंभीर मामला है। जब बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और उनके समाधान में देरी या अस्पष्टता दिखाई देती है तो युवाओं का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से छात्र आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। छात्र और युवा जब ऐसे में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट का संकेत है। यदि सरकार इस संकेत को समझने में विफल रहती है तो यह असंतोष भविष्य में और अधिक व्यापक रूप ले सकता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सरकार का कठोर रुख भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही एक अनिवार्य तत्व होती है। यदि किसी प्रणाली में बार-बार खामियां सामने आती हैं तो जिम्मेदारी तय करना और सुधार के ठोस कदम उठाना आवश्यक होता है लेकिन जब सरकार इन मांगों को नजरअंदाज करती है या उन्हें राजनीतिक रंग देकर खारिज कर देती है तो यह युवाओं के बीच निराशा और गुस्से को और बढ़ाता है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति, जिनकी छवि एक शांत, सकारात्मक और समाधान-उन्मुख कार्यकर्ता की रही है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार और भी अधिक चिंताजनक है। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि उन मूल्यों का भी अपमान है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ भी संवाद के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपनाया जाएगा तो आम नागरिक को क्या संदेश जाएगा? यह भी ध्यान देने योग्य है कि अदालत ने यदि अनशन को समाप्त कराने के निर्देश दिए भी थे तो उसका पालन मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से भी किया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार, जिसमें उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। कानून का पालन आवश्यक है लेकिन उसका क्रियान्वयन भी उतना ही संवेदनशील और मानवीय होना चाहिए।

20 जुलाई को 'चलो संसद' के दौरान जो कुछ हुआ, उसने इस पूरे संकट को और गहरा कर दिया। युवाओं पर बल प्रयोग, उन्हें रोकने के लिए कठोर उपाय और उनके आक्रोश को नियंत्रित करने की कोशिशें यह दर्शाती हैं कि सरकार समस्या के मूल कारणों को समझने के बजाय उसके लक्षणों से लड़ रही है। यह रणनीति अल्पकालिक रूप से भले ही व्यवस्था बनाए रखने में सहायक हो लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह असंतोष को और बढ़ाती है। सवाल यह है कि इस स्थिति का समाधान क्या है? सबसे पहले, सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि समस्या वास्तविक है और उसे केवल राजनीतिक विरोध के रूप में नहीं देखा जा सकता। संवाद की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करना होगा, जिसमें आंदोलनकारियों, छात्रों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। केवल औपचारिक बैठकों से काम नहीं चलेगा बल्कि ठोस और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करने होंगे। दूसरा, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस सुधार आवश्यक हैं। परीक्षाओं की सुरक्षा, मूल्यांकन की निष्पक्षता और परिणामों की विश्वसनीयता को लेकर जो संदेह पैदा हुए हैं, उन्हें दूर करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए तकनीकी उपायों के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार भी जरूरी हैं। तीसरा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अनावश्यक बल प्रयोग से बचना होगा। लोकतंत्र में असहमति को स्थान देना ही उसकी ताकत होती है। यदि हर विरोध को दबाने की कोशिश की जाएगी तो यह लोकतंत्र को कमजोर ही करेगा। सरकार को यह समझना होगा कि असहमति दुश्मनी नहीं होती बल्कि सुधार का अवसर होती है। चौथा, युवाओं के साथ विश्वास का रिश्ता फिर से स्थापित करना होगा। इसके लिए केवल घोषणाएं या बयान पर्याप्त नहीं होंगे, ठोस कार्यवाही और परिणाम दिखाने होंगे। जब युवा यह महसूस करेंगे कि उनकी बात सुनी जा रही है और उस पर कार्रवाई हो रही है, तभी उनका विश्वास लौटेगा।

अंतत:, यह समय सरकार और समाज दोनों के लिए आत्ममंथन का है। क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां असहमति को दबाया जाता है या एक ऐसे लोकतंत्र की ओर, जहां हर आवाज को सम्मान मिलता है? यह निर्णय केवल नीतियों से नहीं बल्कि व्यवहार से तय होगा। सोनम वांगचुक के साथ हुई घटना और उसके बाद का घटनाक्रम एक चेतावनी है कि यदि इसे समय रहते नहीं समझा गया तो यह केवल एक आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक व्यापक जन असंतोष में बदल सकता है। लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता में नहीं बल्कि जनता के विश्वास में होती है। यदि यह विश्वास कमजोर पड़ता है तो सबसे बड़ी हार सत्ता की ही होती है। अब भी समय है कि सरकार संवाद, संवेदनशीलता और समाधान का रास्ता चुने क्योंकि लोकतंत्र में जीत उसी की होती है, जो अपने नागरिकों को साथ लेकर चलता है, न कि उन्हें चुप कराकर।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्याय: (दशम अध्याय)



(गतांक से आगे...)

इतना ही नहीं कौरव वंश की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर को ही देख लीजिये, जहाँ पर कि भारत सम्राट् की विशाल राजधानी थी आज वहाँ खण्डहरों से बने हुये टीले, प्रकृति के परिवर्तन में सम्मिलित होकर सिंह आदि महासत्वों की कर्णकटु भयावह आवाज के साथ गर्जना करते हुये बतला रहे हैं कि संसरणात् संसार:। ऐसी दशा में हम आज पुर, ग्राम, बन, नदी श्रादि का सन्निवेश पुराणवर्णन के विरुद्ध देख कर भी हजारों वर्ष पुराने वर्णनों को जैसे भुठला सकते हैं? प्रत्नतत्त्ववेत्ता भूगर्भ शास्त्री आज राजपूताने के रेगिस्तान (मरुभूमि) को पुराना समुद्र स्थान बताते हुवे सांभर झील को इसका निदर्शक प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाते हैं।

टिप्पणी- इसके जल का स्वाद समुद्र जल सा खारा है, इसके जल से सांभर नमक भी बनता है।

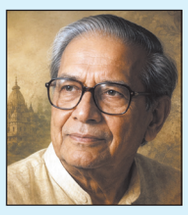
असीरिया के रेगिस्तान को भी (जिसका कि पार करना स्थल मार्ग से तो क्या वैसे भी सर्वथा असम्भव है) समुद्र का आधास स्थान बताते हैं तथा उस भयङ्कर निर्जन प्रदेश में जलीय जन्तुओं की अस्थियों को देख कर अपने विचार की पुष्टि कर रहे हैं। काश्मीर जैसे पर्वतीय प्रदेश की पर्वतमालाओं के भीतर से निकली हुई जलीय जन्तुओं की हड्डियें भी वहां पर प्राचीन समय में जल का होना सिद्ध करती हैं। जब कि समुद्रके स्थान में रेगिस्तान हो जाना तक सम्भव हो सकता है तब क्या पुराणों ने ही कोई पाप किया है कि जो वे (सामन्य वर्णन में वर्तमान वस्तु-स्थिति से विभेद होते ही परित्याज्य समझे जायें?

जो लोग पौराणिक भूगोल पर इस प्रकार के आक्षेप करते हैं, वास्तव में उन सज्जनों ने पौराणिक भूगोल-शैली का गुरुमुख से अध्ययन नहीं किया तथा नांही उन्हें पुराणोक्त भूमण्डल विद्या में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों की सीमा का ही बोध है।

क्रमश: ...

प्रो. चित्र भूषण श्रीवास्तव विदग्ध : एक शांत साधक की उज्ज्वल विरासत

विवेक रंजन श्रीवास्तव



कुछ व्यक्तित्व समय के साथ समाप्त नहीं होते, वे समय का ही हिस्सा बन जाते हैं। उनका जीवन एक तिथि में सिमट सकता है, पर उनकी उपस्थिति नहीं। वे अपनी रचनाओं, अपने विचारों और अपने आदर्शों के रूप में पीढ़ियों तक संवाद करते रहते हैं। प्रो. चित्र भूषण श्रीवास्तव विदग्ध ऐसे ही साहित्य-मनीषी थे। वे जितना बोले, उससे कहीं अधिक लिखा; और जितना लिखा, उससे कहीं अधिक जिया।

25 जुलाई केवल उनकी पुण्यतिथि नहीं है। यह उस साधना को प्रणाम करने का दिन है जिसने लगभग एक शताब्दी तक ज्ञान, संस्कार, साहित्य और मनुष्यता की लौ जलाए रखी। नियति ने उन्हें जन्मशती तक पहुँचने से कुछ ही महीने पहले अपने पास बुला लिया, किंतु शायद शताब्दी वर्षों से नहीं, कृतित्व से पूरी होती है। उस अर्थ में विदग्ध जी अपनी जन्मशती स्वयं अपने साहित्य में जी रहे हैं।

वे उन विरल साहित्यकारों में थे जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बीच कोई दूरी नहीं थी। आज जब शब्दों की चमक अक्सर जीवन की सच्चाई पर भारी पड़ जाती है, तब उनका जीवन विश्वास जगाता है कि साहित्य पहले आचरण में जन्म लेता है, बाद में कागज़ पर उतरता है। सादा जीवन और उच्च विचार उनके लिए कोई उपदेश नहीं था; वह उनकी सहज जीवन-शैली थी। सरल वेश, मितभाषी स्वभाव, अनुशासित दिनचर्या, निरंतर अध्ययन और निष्काम कर्म, यही उनकी पहचान थी।

उन्होंने इतिहास को किताबों में नहीं, जीवन में पढ़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन की आहट सुनी, औपनिवेशिक भारत की बेड़ियाँ देखीं, स्वतंत्र भारत का स्वप्न साकार होते देखा और विज्ञान तथा तकनीक से बदलती दुनिया का विस्मय भी जिया। घोड़े पर डाक लेकर आने वाले डाकिये से लेकर डिजिटल युग तक का यह परिवर्तन उनके अनुभव-संसार का हिस्सा था। इसलिए उनके साहित्य में अतीत की स्मृति है, वर्तमान की सजगता है और भविष्य के प्रति अटूट विश्वास भी। उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए सहज अनुभव होता है कि वे केवल कविता नहीं लिखते थे, वे मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को संबोधित करते थे। उनका राष्ट्रप्रेम किसी राजनीतिक आग्रह का परिणाम नहीं था; वह भारतीय संस्कृति की आत्मा से उपजा हुआ स्वाभाविक भाव था। उनका अध्यात्म संसार से विरक्ति नहीं, संसार के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने की प्रेरणा था। उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना माँ वीणापाणि इसका अप्रतिम उदाहरण है। उसमें वे अपने लिए वैभव, यश या सफलता नहीं माँगते। वे समस्त मानवता के लिए सद्बुद्धि, करुणा, शांति और लोकमंगल की कामना करते हैं। यह कविता वस्तुत: उनके समूचे जीवन-दर्शन का घोष है। वे मानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि ज्ञान है और ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य विश्व-कल्याण।

उनकी साहित्य-साधना का एक विशिष्ट और स्थायी आयाम उनका अनुवाद-कर्म है। वे कहा करते थे—अनुवाद का काम दो भाषाओं का सेतु होता है और अनुवादक इस सेतु का निर्माणकर्ता। यह केवल कथन नहीं, उनकी आजीवन साधना का सार है।

डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और नेतन्याहू की रणनीतिक भूलें

थॉमस एल फ्रीडमैन



डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन भले ही अलग-अलग व्यक्तित्व हों, लेकिन एक बात उनमें समान है कि तीनों खुद को सबसे अधिक समझदार मानते हैं। अफसोस की बात यह है कि एक नेता के तौर पर अपने आसपास चापलूसों की भीड़ इकट्ठी करके उन्होंने सबसे बेवकूफी भरा काम किया है, जिसकी वजह से वे ऐसी बेकार की लड़ाइयों में फंस गए हैं, जिनसे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अब अपनी गलती मानकर शर्मिंदगी झेलना ही है।

बात इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शुरू करते हैं। नेतन्याहू का रास्ता भटकना और साथ ही मशहूर इस्राइली खुफिया एजेंसी 'मोसाद' के नेतृत्व को भी गुमराह कर देना उनके दो ऐसे फैसलों से साफ झलकता है, जो पूरी तरह बेतुके थे। पहला, यह विश्वास कि इस्राइल हवाई हमलों के दम पर तेहरान की सरकार को गिरा सकता है; और दूसरा, यह कि वह ईरान का नया नेता तय कर सकता है। फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई बैठक में नेतन्याहू और मोसाद के तत्कालीन निदेशक डेविड बार्निया ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया था कि अगर इस्राइल और अमेरिका ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या कर दे, तो वहां की सरकार गिर जाएगी और अच्छे लोग सत्ता संभाल लेंगे। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मान लिया था कि ईरान उसी तरह उनके हाथों में आ जाएगा, जैसे निकोलस मादुरो को हटाने के बाद वेनेजुएला आया था। इस्राइल का यह सोचना कि वह अहमदीनेजाद को सत्ता में बिठा सकता है और यह कि ईरानी समाज उन्हें स्वीकार कर लेगा, पूरी तरह से पागलपन ही है।

ट्रंप और नेतन्याहू, पुतिन की तरह ही सोच रखते हैं। पुतिन ने खुद अपनी ही बनाई गलतफहमी पर यकीन कर लिया था कि यूक्रेन के लोग फिर से 'मदर रशिया' का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं और कीव में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार आसानी से गिर जाएगी। सैन्य विश्लेषक रॉबिन लेयर्ड ने कहा कि ईरान में जो हुआ था, ठीक वैसा ही वहां भी हुआ था। ऐसा लगता है कि रूसी खुफिया विभाग ने 'यूक्रेन के लोगों की सोच और उनकी क्षमताओं के बारे में जमीनी हकीकत बताने के बजाय, रूस-समर्थक सूत्रों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जिन्होंने मॉस्को को वही बातें बताईं, जो वह सुनना चाहता था।'

हमास, हिज्बुल्ला और तेहरान के खिलाफ रणनीतिक जीत के बावजूद, नेतन्याहू इनमें से किसी को भी इस्राइल के लिए एक नई रणनीतिक हकीकत में नहीं बदल पाए हैं। इसके लिए उन्हें यह साफ करना होगा कि गाजा, लेबनान व ईरान में उनके सैन्य अभियानों का मकसद इलाके को इस्राइली-फलस्तीनी शांति के लिए सुरक्षित बनाना था। मगर, दुनिया देख रही है कि नेतन्याहू गाजा और वेस्ट बैंक को इस्राइल में मिलाने के लिए इस इलाके को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हासिल करने के लिए वह बाकी सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं-जैसे सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करना, कई युवा अमेरिकियों, डेमोक्रेटिक पार्टी और पश्चिमी यूरोप का समर्थन तथा इस्राइल की न्यायपालिका की आजादी आदि।

इस बीच, बिना किसी सहयोगी, बिना अंतरराष्ट्रीय मंजूरी और बगैर किसी 'प्लान बी' के ईरान पर हमला करके ट्रंप ने अमेरिका को कमजोर और अलग-थलग कर दिया है। इस फैसले से तेहरान की तबाही मचाने वाले हथियार विकसित करने की क्षमता खत्म नहीं हुई। उलटे, ट्रंप ने ईरान को बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के दो बेहद सस्ते और प्रभावी हथियार थमा दिए- पहला, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण का विकल्प; और दूसरा, जब भी ट्रंप ईरान पर बमबारी करें, तब फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बनाने की क्षमता।

पुतिन ने रूस के कमजोर लोकतंत्र को एक ऐसे पुलिसराज में बदल दिया है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल व गैस पर टिकी है और कमजोर है। आज, एआई क्रांति में रूस का कहीं कोई नामो-निशान नहीं है। यह कुछ वैसा ही है, जैसे कार का आविष्कार होने पर पुतिन ने घोड़ों में निवेश करना ज्यादा पसंद किया हो और साथ ही, एक एकजुट रूसी मातृभूमि वाली अपनी 19वीं सदी की कल्पना को भी बनाए रखा हो।

आज हमारे सामने तीन वैश्विक नेता हैं, जो अपनी ही गलतफहमियों के भंवर में कुछ इस तरह फंस चुके हैं, जिनसे निकलने का उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वे उस संकट से बाहर निकलने का उपाय भी बमबारी में ही तलाश रहे हैं। हमें उन टेढ़ी सोच वाले, निराशावादी और अयोग्य नेताओं को नहीं भूलना चाहिए, जो 1979 से ईरान चला रहे हैं। वे भी ऐसी ही स्थिति में फंसे हैं, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। अपनी काबिल जनता को सशक्त बनाने के बजाय, ईरान के धार्मिक तानाशाहों ने विरोधियों को गोलियों से चुप कराकर, लोगों पर कट्टरपंथी इस्लाम थोपकर और इस्राइल को मिटाने की कोशिश में अरबों डॉलर बर्बाद करके पिछले 47 वर्षों तक सत्ता में बने रहने का रास्ता चुना। उम्मीद है कि एक दिन वहां के लोग खुद ही उन्हें सत्ता से हटा देंगे, शायद किसी ऐसी ताकत की मदद से, जिसकी किसी को उम्मीद न हो और जो कोई देश भी न हो।

ईरान के नेताओं ने अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बेपरवाही से पर्यावरण का जबर्दस्त दोहन किया और बहुत-सी नदियों पर बांध बनाए। अब वे ट्रंप या नेतन्याहू से भी कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने पूरी तरह कमजोर पड़ गए हैं और वह है कुदरत। ईरान के भविष्य को लेकर सबसे भयावह चेतावनी सात महीने पहले बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स में प्रकाशित एक विश्लेषण में दी गई थी। इसमें कहा गया था कि देश का गहराता जल संकट संभवत: ईरानी संस्थानों को ठप करने में इस्राइल और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों से भी अधिक विनाशकारी साबित होगा। विश्लेषकों ने कहा, '2025 की गर्मियों में ईरान में जबर्दस्त गर्मी की लहर (हीट वेव) चली। तेहरान समेत कई इलाकों में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिससे सरकारी दफ्तरों और बैंकों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इस दौरान, तेहरान को पानी आपूर्ति करने वाले बड़े जलाशयों का जलस्तर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ, तो राजधानी को खाली भी करना पड़ सकता है।'

कुल मिलाकर, आखिरकार ये टकराव बातचीत से ही खत्म होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी नेता अपनी बेवकूफी भरी लड़ाइयां लंबे समय तक नहीं लड़ सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि वह समय कब आएगा, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे स्वीकार करेंगे कि टकराव के बजाय बातचीत ही सही रास्ता था।

आज का इतिहास

1909 फ्रांसीसी एविएटर लुइस ब्लेयर ने इंग्लैंड के कैलाइस, फ्रांस, टोडवर, इंग्लैंड के पास से उड़ान भरते हुए, एहीवियर-से-एयर फ्लाइंग मशीन में अंग्रेजी चैनल को पार किया।

1938 फ़िलिस्तीन की एक मंडी में दो बम विस्फोटों में 62 असैनिक मारे गये और लगभग 100 अन्य घायल हो गये।

1957 फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक साल से अधिक समय बाद, ट्यूनीशिया ने अपने राजशाही, हुसैनिद राजवंश को समाप्त कर दिया, और रिपब्लिक बन गया।

1978 लुईस ब्राउन, इन विट्रोफर्टिलाइजेशन के माध्यम से गर्भ धारण करने वाली दुनिया की पहली बच्ची का जन्म इंग्लैंड के ओल्डहैम में हुआ था।

1978 दो प्यूर्टो रिकान स्वतंत्रता-समर्थक कार्यकर्ताओं को विलबा में सेरो मैराविला में उपचुनाव में मार दिया गया था।

1993 जायोनी शासन के सैनिकों ने दोबारा दक्षिणी लेबनान पर जल थल और वायु आक्रमण किया।

1994 जॉर्डन और इजरायल के बीच 46वर्षों से चल रहा युद्ध समाप्त हुआ।

2000 एयर फ्रांस का कॉनकॉर्ड विमान उड़ान भरने के दो मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें 113 लोगों की मौत हुई।

2010 विकीलीक्स ने अफगानिस्तान में युद्ध के बारे में 75,000 वर्गीकृत दस्तावेजों को प्रकाशित किया, जो अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे बड़े लीक में से एक था।

2011 साइकिल चालक अल्बर्टो कोंटाडोर ने 2010 टूर डी फ्रांस जीता, जबकि सात बार के विजेता, लांस आर्मस्ट्रांग ने अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की।

2013 ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने बिल्लियों को मानव एलर्जी पैदा करने वाले तंत्र की पहचान की है; उनका मानना है कि हालत के लिए एक सामान्य इलाज अगले पांच वर्षों में उपलब्ध हो सकता है।

2013 बढ़ती हुई औद्योगिक मंदी के बीच, चीन अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयास में व्यापार कर को तोड़ता है और उदारीकरण का निर्यात करता है।

2014 मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 की मिसाइल स्ट्राइक में शवों और सबूतों की तलाश में डच और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस पूर्वी यूक्रेन की ओर जा रही है; अलगाववादियों पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।

2014 बोस ने शोर-रद्द प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न पेटेंटों के उल्लंघन के लिए बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

सवालों से घिरा लोकतंत्र, सड़कों पर युवा

कुमार कृष्णन

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं होती कि सत्ता बहुत शक्तिशाली हो जाती है; वह तब पैदा होती है, जब समाज प्रश्न पूछना छोड़ देता है। नागरिकों की चुप्पी, विश्वविद्यालयों का मौन और युवाओं का केवल निजी सफलता तक सीमित हो जाना किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होता। इसके विपरीत, जब युवा व्यवस्था से जवाब मांगते हैं, तब वह केवल विरोध नहीं होता; वह लोकतंत्र की आत्मा के भीतर उठती नई हलचल का संकेत होता है।

देश में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और रोजगार के प्रश्नों को लेकर उभरे छात्र-युवा आंदोलन को इसी व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। इसे केवल किसी एक परीक्षा, किसी एक पेपर लीक या किसी एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित कर देना उसकी प्रकृति को छोटा कर देना होगा। यह उस पीढ़ी की बेचैनी है जिसने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, रोजगार की अनिश्चितता झेली और अब अपनी मेहनत से अधिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए विवश हो रही है।

दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन कुछ ही दिनों में अनेक राज्यों तक फैल गया। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई ने इस बहस को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया। लाठीचार्ज, आँसू गैस, घायल छात्र और तनावपूर्ण हालात ने एक मूलभूत प्रश्न सामने रखा—क्या लोकतंत्र में असहमति का पहला उत्तर पुलिस बल होना चाहिए, या संवाद का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए?

निस्संदेह, कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार का दायित्व है। यदि हिंसा होती है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है तो प्रशासन हस्तक्षेप करेगा ही। लेकिन लोकतंत्र की परिपक्वता का आकलन केवल इस बात से नहीं होता कि उसने कानून कैसे लागू किया; उससे भी अधिक इस बात से होता है कि उसने असंतोष को समय रहते सुना या नहीं। संवाद की विफलता अक्सर टकराव का पहला कारण बनती है।

इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसने नई पीढ़ी को लेकर बनी कई रूढ़ धारणाओं को तोड़ दिया है। लंबे समय से कहा जाता रहा कि आज का युवा केवल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और निजी करियर तक सीमित है। लेकिन जंतर-मंतर, पटना और देश के अनेक शहरों में दिखाई देने वाली भीड़ ने इस धारणा को चुनौती दी। हजारों छात्र-छात्राएँ अपनी पढ़ाई, नौकरी और निजी सुविधाएँ छोड़कर सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में युवतियों की सक्रिय भागीदारी ने इस आंदोलन को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया। अनेक युवतियों ने कहा कि आंदोलन के बीच उन्हें बराबरी, सम्मान और सुरक्षा का अनुभव हुआ। किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की नैतिक शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण शायद ही हो।



यह मान लेना भी भूल होगी कि यह असंतोष अचानक पैदा हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि वर्षों से तैयार हो रही थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर उठते सवाल, भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार विलंब, बेरोज़गारी का दबाव, शिक्षा की बढ़ती लागत और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना—इन सबने मिलकर युवाओं के भीतर गहरा अविश्वास पैदा किया है। जब किसी समाज का परिश्रमी युवा अपनी प्रतिभा से अधिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे, तब यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं रहती; यह लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसे का संकट बन जाती है।

पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का बड़ा हिस्सा धार्मिक, सांस्कृतिक और पहचान आधारित मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। इन विषयों का अपना महत्व है, लेकिन इसी दौरान शिक्षा, विश्वविद्यालयों, शोध, रोजगार और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता जैसे प्रश्न धीरे-धीरे सार्वजनिक बहस के हाशिए पर चले गए। वर्तमान छात्र आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शायद यही है कि उसने राष्ट्रीय विमर्श को फिर उन प्रश्नों की ओर मोड़ दिया है, जिनका सीधा संबंध करोड़ों युवाओं के भविष्य से है।

इतिहास बताता है कि जब भी युवाओं ने अपने समय के बुनियादी प्रश्नों को लेकर आवाज़ उठाई है, तब राजनीति को अपनी भाषा बदलनी पड़ी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक गति दी। 1974 के छात्र आंदोलन ने लोकतंत्र और जवाबदेही की बहस को नई दिशा दी। मंडल आंदोलन ने सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्रीय प्रश्न बनाया। हर दौर का अपना एजेंडा था, लेकिन एक बात समान रही—युवाओं ने राजनीति को उसकी सुविधाजनक सीमाओं से बाहर निकलने के लिए बाध्य किया। आज का प्रश्न शिक्षा, रोजगार और अवसरों की निष्पक्षता का है। संभव है कि आने वाले वर्षों में यही प्रश्न भारतीय राजनीति की दिशा भी तय करें।

युवा आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे केवल तात्कालिक घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं होते, बल्कि व्यवस्था के भीतर लंबे समय से जमा असंतोष का सार्वजनिक विस्फोट होते हैं। आज शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और रोजगार के प्रश्न पर उभरे छात्र-युवा आंदोलन को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इसे केवल किसी एक परीक्षा, किसी एक पेपर लीक या किसी एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित करके समझना भूल होगी। यह उस पीढ़ी की सामूहिक व्यथा है, जिसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, बेरोज़गारी का दबाव झेला और अब अपनी मेहनत की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े होते देख रही है।

दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन कुछ ही दिनों में कई राज्यों तक फैल गया। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव ने इस बहस को और तीखा बना दिया। लाठीचार्ज, पथराव, आँसू गैस और घायल छात्रों की तस्वीरों ने पूरे देश के सामने एक बुनियादी प्रश्न रख दिया—क्या लोकतंत्र में असहमति का उत्तर केवल पुलिस बल है, या संवाद की परंपरा अभी भी जीवित है?

लोकतांत्रिक शासन में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का दायित्व है। यदि हिंसा होती है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले यह पूछना भी उतना ही आवश्यक है कि क्या संवाद के सभी रास्ते समाप्त हो चुके थे? क्या छात्रों की आशंकाओं और मांगों को समय रहते गंभीरता से सुना गया? लोकतंत्र की सफलता केवल व्यवस्था बनाए रखने में नहीं, बल्कि असंतोष को हिंसा में बदलने से पहले उसे संवाद में बदल देने की क्षमता में निहित होती है।

इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसने उस धारणा को चुनौती दी है जिसके अनुसार नई पीढ़ी केवल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और निजी करियर तक सीमित हो चुकी है। जंतर-मंतर से लेकर पटना, भागलपुर, मुंगेर,लखनऊ, जयपुर, भोपाल और दूसरे शहरों तक दिखाई देने वाली भीड़ ने साबित किया कि यह पीढ़ी केवल डिजिटल नागरिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नागरिक भी है। हजारों छात्र-छात्राएँ अपनी कक्षाएँ छोड़कर, नौकरी से अवकाश लेकर और कई मामलों में पारिवारिक असहमति के बावजूद सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में युवतियों की भागीदारी ने इस आंदोलन को एक नया सामाजिक आयाम दिया।

यह मान लेना भी भूल होगी कि यह आक्रोश अचानक पैदा हुआ है। इसकी जड़ें पिछले कई वर्षों में विकसित हुई परिस्थितियों में हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं पर बार-बार उठते प्रश्न, भर्ती प्रक्रियाओं में लंबा विलंब, बेरोज़गारी का बढ़ता दबाव, शिक्षा का महँगा होना और अवसरों की असमानता—इन सबने मिलकर युवाओं के भीतर गहरा अविश्वास पैदा किया है। जब किसी समाज में मेहनत करने वाले युवा अपनी योग्यता से अधिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगें, तो यह केवल प्रशासनिक संकट नहीं रह जाता; यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति भरोसे का संकट बन जाता है।

समाधान की राह में फंसा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का कांटा

हिमांशु मिश्र



नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल इस मामले में जहां विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने लंबी लड़ाई की रणनीति तैयार की है, वहीं सरकार भी प्रधानमंत्री की घोषणाओं के असर का आकलन कर आगे बढ़ने की तैयारी में है। फिलहाल सरकार के समाधान के प्रयास की राह में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ा कांटा बनकर उभरा है। विपक्ष संसद में इस्तीफे के बिना चर्चा के लिए तो सीजेपी इसके बिना सरकार से संवाद के लिए तैयार नहीं है।

मौजूदा नीट पेपर लीक, यूजीसी की विवादास्पद गाइड लाइन व एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी पाठ्यक्रम के कारण प्रधान कई बार सरकार के लिए मुसीबत बने। उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में कम से कम प्रधान के विभाग में बदलाव तय है। हालांकि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के तूल पकड़ने के बाद सरकार की रणनीति किसी भी सूरत में विपक्ष को श्रेय देने की नहीं है। सरकार की पहली कोशिश संवाद और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का संदेश देकर समाधान निकालने पर है।

इस मुद्दे पर बदली राजनीतिक परिस्थितियों में सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष और सीजेपी के रुख में बड़ा बदलाव आया है। पहले संवाद से पूरी तरह दूरी बरत रही सरकार अब संवाद, चर्चा के साथ कार्रवाई के जरिये बीच का रास्ता निकालना चाहती है। दूसरी ओर पहले चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष अब इससे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहता है। पहले खुद सरकार के द्वार पहुंची सीजेपी अब न सिर्फ प्रधान का इस्तीफा चाहती है, बल्कि सरकार से अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहती है।

सरकार के रणनीतिकारों को लगा था कि सोनम वांगचुक के उस पत्र से बदलाव की स्थिति बनेगी, जिसमें उन्होंने संसद में चर्चा कराने, आंदोलनकारी छात्रों पर मुकदमा दर्ज न करने की शर्त रखी थी। सरकार की योजना थी कि सीजेपी से बातचीत के बाद उनकी शर्तें मान ली जाएगी। इसके तहत सरकार दो दिनों से इस मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव दे रही है। हालांकि, विपक्ष ने अपना रुख बदलते हुए प्रधान के इस्तीफे की शर्त रखी है।

सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कर विपक्ष को श्रेय नहीं देना चाहती। इसके अलावा, यूजीसी के विवादास्पद जाति संबंधी गाइडलाइन ने विद्यार्थी वर्ग को दो हिस्से में बांट दिया था। इनमें ओबीसी छात्र इस गाइडलाइन के समर्थन में थे। सरकारी सूत्र ने कहा, इसी कारण सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में कांग्रेस के इतर लाइन लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं की।

क्या बांकीपुर में छात्र आंदोलन लिखेगा उपचुनाव की नई पटकथा?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बिहार की राजनीति में उपचुनाव अक्सर स्थानीय समीकरणों, संगठन की ताकत और उम्मीदवार की लोकप्रियता के आधार पर तय होते हैं। लेकिन पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव इन परंपरागत सीमाओं से आगे निकल गया है।

यह चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब देश के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली और बिहार में, प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के अधिकारों को लेकर आंदोलन जारी है। पुलिस कार्रवाई, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और संसद से लेकर सड़क तक चल रही बहस ने इस उपचुनाव को एक व्यापक राजनीतिक संदर्भ दे दिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है। पहली नजर में यह एक सामान्य उपचुनाव लग सकता है, लेकिन यदि इसके सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को देखा जाए तो यह राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक साबित हो सकता है।

बांकीपुर को बिहार की सबसे शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक विधानसभा सीटों में गिना जाता है। यहां बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, व्यवसायी, सेवानिवृत्त अधिकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। यह क्षेत्र केवल जातीय समीकरणों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि शिक्षा, प्रशासन, सुशासन, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट राय रखता है।

इसी कारण छात्र आंदोलन का प्रभाव यहां अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में अधिक महसूस किया जा सकता है। यदि किसी चुनाव में शिक्षित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो बांकीपुर उनमें सबसे प्रमुख उदाहरणों में शामिल है।

हर आंदोलन सीधे वोट में नहीं बदलता। लेकिन हर बड़ा आंदोलन मतदाताओं की मनोस्थिति को अवश्य प्रभावित करता है। जब युवा लगातार सड़कों पर हों,



प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हों और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हों, तब उसका असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है जो शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों को गंभीरता से देखता है।

बांकीपुर में ऐसे मतदाताओं की संख्या कम नहीं है। इसलिए यह मानना कठिन होगा कि छात्र आंदोलन का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रभाव कितना होगा, किस दिशा में जाएगा और किस दल को लाभ पहुंचाएगा, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस उपचुनाव का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का चुनाव मैदान में उतरना है। उन्होंने पिछले कई वर्षों से शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव को अपने अभियान का प्रमुख आधार बनाया है। यदि छात्र आंदोलन चुनावी विमर्श का हिस्सा बनता है तो उसके साथ सबसे स्वाभाविक राजनीतिक संवाद स्थापित करने की कोशिश प्रशांत किशोर करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वह चुनाव को स्थानीय विकास, संगठन और अपने पारंपरिक समर्थन आधार तक सीमित रखे। यही कारण है कि यह चुनाव केवल भाजपा बनाम जन सुराज का नहीं, बल्कि दो अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों का मुकाबला भी बन गया है।

यह सीट वर्षों से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है। नितिन नवीन लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे हैं और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका इस्तीफा इस उपचुनाव का कारण बना है। स्वाभाविक है कि भाजपा इसे केवल एक सीट नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर लड़ रही है। यदि पार्टी यह सीट आराम से जीतती है तो संदेश जाएगा कि छात्र आंदोलन और विपक्षी राजनीति का प्रभाव सीमित रहा। लेकिन यदि मुकाबला अपेक्षा से अधिक कड़ा होता है या परिणाम अप्रत्याशित आता है, तो उसके राजनीतिक अर्थ केवल बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेंगे।

बिहार की राजनीति लंबे समय तक जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाएं, रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे युवाओं के बीच नई राजनीतिक चेतना पैदा कर रहे हैं। बांकीपुर जैसे शिक्षित शहरी क्षेत्र में यह परिवर्तन और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यहां मतदाता उम्मीदवार की सामाजिक पहचान के साथ-साथ उसकी राजनीतिक दृष्टि, प्रशासनिक क्षमता और शिक्षा संबंधी सोच को भी महत्व देता है।

इसलिए संभव है कि इस बार चुनावी चर्चा का केंद्र जातीय समीकरणों के साथ-साथ छात्र आंदोलन भी बने।

30 जुलाई को पड़ने वाला प्रत्येक वोट केवल एक विधायक का चुनाव नहीं करेगा। वह यह भी बताएगा कि क्या छात्र आंदोलन चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, क्या शिक्षित मतदाता राष्ट्रीय बहसों को स्थानीय चुनावों में महत्व देते हैं और क्या बिहार की राजनीति में मुद्दा आधारित मतदान की गुंजाइश बढ़ रही है।

संभव है कि परिणाम भाजपा के पक्ष में जाए। यह भी संभव है कि विपक्ष या नया राजनीतिक विकल्प बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन परिणाम चाहे जो हो, यह चुनाव सभी राजनीतिक दलों को एक संदेश अवश्य देगा कि शिक्षित समाज और युवा मतदाता अब केवल दर्शक नहीं हैं। वे अपने समय के सवालों को मतदान केंद्र तक ले जाने की क्षमता रखते हैं।

बांकीपुर का उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां केवल मतों की गिनती नहीं होगी, बल्कि यह भी परखा जाएगा कि लोकतंत्र में छात्र आंदोलन की प्रतिध्वनि मतदान मशीन तक पहुंचती है या नहीं। शायद यही इस उपचुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश होगा।

परीक्षा व्यवस्था के संकट से लोकतांत्रिक टकराव तक

राज कुमार सिन्हा

भारत में शिक्षा और सार्वजनिक भर्ती परीक्षा प्रणाली को लेकर उपजा असंतोष अब एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले लगभग एक महीने से हजारों छात्र-छात्राएं और युवा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में गहराते संकट के लिए जवाबदेही तय की जाए तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल की जाए। पिछले एक दशक में देशभर में केंद्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के 90 से अधिक पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं, जिनसे लगभग 7.5 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। इनमें नीट-यूजी, यूजीसी-नेट, एसएससी तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। भारत की 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 34.5 से 37.1 करोड़ युवा आबादी, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत है, इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। बार-बार परीक्षाओं के निरस्त होने, नियुक्तियों में देरी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है। हर रद्द हुई परीक्षा और हर प्रश्नपत्र लीक के पीछे वर्षों की मेहनत, परिवारों का आर्थिक निवेश, मानसिक तनाव और टूटते सपने जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि यह आंदोलन केवल परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के रोजगार, महंगाई और भविष्य की सुरक्षा जैसे व्यापक प्रश्नों से भी जुड़ गया है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर तीन सप्ताह से आमरण अनशन कर रहे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनसमर्थन मिला। इसके बाद छात्रों ने संसद तक मार्च का आह्वान किया।दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलुरु सहित अनेक शहरों में कैंडल मार्च, धरने और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। सिख समाज सहित अनेक



सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में आम नागरिक भी भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री भेजकर आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। इस मानवीय सहयोग ने आंदोलन को सामाजिक संवेदना का भी स्वरूप प्रदान किया है।20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज तथा अन्य बल प्रयोग के माध्यम अपनाए। अनेक प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके विरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सादे कपड़ों में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की तथा बैरिकेडिंग में करंट और कीलों वाली लाठियों का प्रयोग किया गया। पुलिस पर पैलेट गन के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है। सरकार ने जंतर-मंतर क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए, कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया तथा पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया। केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शनों को संभालने के लिए 3000 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मी भेजे हैं। यह कदम दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर उठाया गया है।राजधानी के संवेदनशील हिस्सों जंतर-मंतर से संसद भवन तक खासतौर से इसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है. यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जमीनी घेराबंदी के अलावा दिल्ली की सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से पूरी तरह से लैस किया गया है। इसके बावजूद अगले दिन भी बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन स्थल पर पहुंचे और संघर्ष जारी रखने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया और गिरफ्तार हुए। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सहित कई नेताओं ने जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। संसद में भी विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई मानवाधिकार संगठनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग पर चिंता व्यक्त की और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपनी बात रखने तथा धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया की नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही स्थापित करने की है। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई, भर्ती प्रक्रियाओं की समयबद्धता, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में जवाबदेही तय करना तथा शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करना शामिल है।यह आंदोलन अब केवल परीक्षा सुधार का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं के भविष्य, रोजगार और शासन की जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। यदि सरकार आंदोलनकारी छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय लेती है, तो स्थिति शांत हो सकती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का रास्ता खुल सकता है। इसके विपरीत यदि केवल पुलिस बल और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से आंदोलन को दबाने का प्रयास जारी रहता है, तो युवाओं का असंतोष और व्यापक हो सकता है।

छात्रों के भविष्य पर सियासत का संग्राम

कांतिलाल मांडोत

देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद का उद्देश्य सरकार से जवाब मांगना, कानून बनाना और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना है। वहीं लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब संसद का बहुमूल्य समय लगातार हंगामे की भेंट चढ़ने लगे और सड़क पर चल रहे आंदोलनों का स्वर समाधान से अधिक राजनीतिक टकराव का प्रतीक बन जाए, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है। इसका सीधा उत्तर है—देश के छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों का। नीट पेपर लीक का मामला अत्यंत गंभीर है। करोड़ों परिवारों की उम्मीदें प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी होती हैं। यदि परीक्षा की गोपनीयता भंग होती है तो केवल प्रश्नपत्र नहीं लीक होता, बल्कि लाखों विद्यार्थियों का विश्वास भी टूटता है। इसलिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। सरकार ने संसद में यह भी कहा कि वह इस विषय पर किसी भी दिन और किसी भी अवधि की चर्चा के लिए तैयार है। इसके बावजूद संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बना रहा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को चर्चा की पूर्व शर्त बना दिया। संसद के बाहर इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसद आमने-सामने आ गए। नारेबाजी हुई, आरोप-प्रत्यारोप हुए और दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन यदि संसद ही चर्चा का मंच न बन सके तो फिर जवाबदेही किस प्रकार तय होगी। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। यह उनका राजनीतिक अधिकार है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है और चर्चा के लिए वह तैयार है। ऐसे में लोकतांत्रिक परंपरा यही अपेक्षा करती है कि पहले संसद में खुली बहस हो, तथ्यों पर चर्चा हो और उसके बाद राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जाएं। यदि हर विषय पर पहले इस्तीफे की शर्त रखी जाएगी तो संसदीय विमर्श की परंपरा कमजोर होगी। वर्तमान घटनाक्रम का दूसरा पक्ष जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरी तरह वैध है, लेकिन जब किसी आंदोलन के दौरान हिंसा, पुलिस से टकराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आम नागरिकों के जीवन को बाधित करने जैसे आरोप सामने आते हैं, तब आंदोलन की नैतिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यदि किसी प्रदर्शन में कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस का कर्तव्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं पुलिस की कार्रवाई भी कानून के दायरे में और निष्पक्ष होनी चाहिए। दोनों पक्षों की जवाबदेही लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भी देख रहा है। छात्र और युवा हर चुनाव में महत्वपूर्ण मतदाता होते हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल स्वयं को युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी दिखाना चाहता है। यही कारण है कि नीट का मुद्दा केवल परीक्षा व्यवस्था तक सीमित न रहकर राजनीतिक संघर्ष का प्रमुख विषय बन गया है। लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या छात्रों की वास्तविक समस्याएं केंद्र में हैं या राजनीतिक लाभ? इतिहास भी बताता है कि परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाएं केवल किसी एक सरकार या एक राजनीतिक दल के कार्यकाल तक सीमित नहीं रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक तथा धांधली के मामले सामने आए थे।

महाभारत कथा : भगवान कृष्ण का अवतरण यदु- कुल में

कुरु-वंश और यदु-वंश से जुडी इस श्रृंखला में आज पढते हैं, यदु वंश की शुरुआत के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे मेंज



सद्गुरु : यदु को उसके पिता ययाति ने श्राप दिया था कि वह कभी राजा नहीं बन सकता। वह दक्षिण की ओर आज के मथुरा शहर चला आया और नागा जनजाति में विवाह कर लिया। उस जनजाति में राजा नहीं होतेथे, एक परिषद शासन चलाती थी।यदु उस शासक परिषद में शामिल हो कर उसका मुखिया बन गया। उसके बच्चों से अलग-अलग वंश परंपराएं निकलीं जैसे अंधक, भोजक और वृष्णि, जो साथ मिलकर यादवों के नाम से मशहूर हुईं।

कुछ पीढियों के बाद यदु वंश में वासुदेव का जन्म हुआ। उनकी दो पत्नियां, देवकी और रोहिणी थीं। देवकी का एक सौतेला भाई था, कंस, जो जबरन बनाए गए संबंध यानी बलात्कार से पैदा हुआ था। उन दिनों हर कहीं यह परंपरा थी कि चाहे बच्चे का जन्म किसी भी तरह हुआ हो, वह अपनी मां के वंश का एक वैध हिस्सा बन जाता था। मगर यादवों ने कंस को नहीं अपनाया और उसे अवैध सन्तान कहकर दुत्कार दिया। वह एक महान योद्धा था, फिर भी उन्होंने उसे शासक परिषद में शामिल करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह बहुत दुष्ट और असभ्य था। कंस ने पूरब के एक महान राजा जरासंध से दोस्ती कर ली। जरासंध के समर्थन के कारण बहुत से लोग कंस के साथ हो गए। यादव वंश में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने बुजुर्गों की परिषद को खारिज करके खुद को राजा घोषित कर दिया था। राजा बनने के बाद कंस ने अपनी निर्विवाद सत्ता स्थापित कर ली और अपने असभ्य तरीकों से राजपाट चलाने लगा। उसके शासन में लोग काफी दुखी थे, मगर कोई उसका विरोध करने का साहस नहीं करता था क्योंकि उसका मित्र जरासंध एक शक्तिशाली राजा था। कंस को श्राप मिला हुआ था कि उसकी बहन के आठवें बच्चे के हाथों उसका वध होगा। जब उसे इस बात का पता चला, तो उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। वह गिनती करके सिर्फ आठवें बच्चे को मार सकता था मगर वह कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। जिस दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ, कंस ने जेल में जाकर नवजात शिशु को पैरों से उठाया और फर्श पर पटक दिया। उसकी मां भय और दुख से हक्की-बक्की रह गई, मगर जेल में कैद होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकते थे। अगले बच्चे का जन्म हुआ, कंस ने फिर से आकर उसे पटक कर मार डाला। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वासुदेव और देवकी ने यह सुनिश्चित किया कि सातवां बच्चा बलराम, वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला जाए , जो नदी के दूसरी ओर गोकुल में रहती थी।

भगवान कृष्ण का अवतरण

फिर आठवें बच्चे कृष्ण का जन्म होना था। वे इस बच्चे को बचाने के लिए पूरी तरह संकल्पित थे, सिर्फबच्चे के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि वे कंस के अत्याचार को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने तंत्र विद्या से जेल के रक्षकों को सुला दिया। गोपों के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा नदी के उस पार रहते थे। यशोदा ने अभी-अभी एक बच्ची को जन्म दिया था। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को नंद और यशोदा को सौंप दिया और उस नवजात बच्ची को अपने साथ जेल में ले गए। सुबह जब कंस जेल में आया तो लडकी को देखकर हैरान रह गया क्योंकि आठवां बच्चा लडका होना चाहिए था, जो उसे मारता। मगर फिर भी कंस अपने जीवन पर कोई खतरा नहीं चाहता था। कौन जाने लडकी कब लडके में बदल जाए।

वह उसे उठाने ही वाला था कि देवकी ने उससे प्रार्थना की, 'देखो, यह तो एक लडकी है। यह तुम्हें नहीं मार सकती। इसकी शादी हो जाएगी और यह अपने घर चली जाएगी। कृपया इसका जीवन बख्श दो।' कंस ने कहा, 'ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं कोई खतरा क्यों मोल लूं' वह लडकी को उठाकर उसे पटकने ही वाला था, मगर वह नीचे नहीं गिरी।

मां सिद्धिदात्री का स्वरूप

मां सिद्धिदात्री मां का नवां स्वरूप हैं। नवरात्रि के नौंवे दिन मां के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री देवी की आराधना करने से आपकी योग्यता और शक्ति में बढोतरी होती है। मां का यह स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में भी विख्यात है।



पूजन विधि कंडे (गाय के गोबर के उपले) जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोडा, पान, सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किसमिस, कमलगट्टा अर्पित करें। नवरात्र के नौंवे दिन हवन में मां सिद्धिदात्री की इन मंत्रों के उच्चारण के साथ पूजा करें।

मां सिद्धिदात्री का स्वरूप

सिद्धिदात्री के चार हाथ हैं। एक हाथ में उन्होंने चक्र धारण किया हुआ है और दूसरे हाथ में गदा है। तीसरे हाथ में शंख है तो चौथे हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। मां सिद्धिदात्री कमल के फूल पर आसीन हैं। इनका वाहन सिंह है। ऐसा माना जाता है की मां का यह स्वरुप भक्त की 26 अलग-अलग मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार मां सिद्धिदात्री की पूजा से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी आठ सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। ब्रम्हावैवर्त पुराण के श्रीकृष्ण जन्मखंड के अनुसार मां सिद्धिदात्री की पूजा से 18 तरह की सिद्धियों का आशीर्वाद पाया जा सकता है। देव, दानव, गन्धर्व, किन्नर, मानव, यक्ष, सभी मां सिद्धिदात्री की आराधना करके आशीर्वाद पाते हैं।

नौंवे दिन हवन में मां सिद्धिदात्री के इस मंत्र का उच्चारण करें -

ऊँ हीं सः सिद्धिदात्यै नमः।।

भक्त की 26 अलग मनोकामनाओं को पूरा करती हैं मां

मां की आराधना से मिलती हैं सिद्धियां

भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्द्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। विधि-विधान से नौंवे दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह अंतिम देवी हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।

वास्तु विज्ञान भारत का अत्यंत प्राचीन ज्ञान है

सब सही होते हुए भी कभी कभी हमें परेशानियों का सामना करना पडता है, ऐसा क्यों क्या ये सब कहीं वास्तु दोष के कारण तो नहीं है । इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में खूब सफलता प्राप्त करें । उसे धन, यश, ऐश्वर्य, प्रसन्नता, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य सभी कुछ प्राप्त हो, इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है, सदैव प्रयत्नशील रहता है लेकिन फिर भी सभी को उपरोक्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं ही होती है । कई बार जब बहुत जी तोड मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, जीवन में अस्थिरता रहती है या कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है तो व्यक्ति निराश होने लगता है । लेकिन इसका कारण उसके भवन, कार्यालय स्थल का वास्तु दोष हो सकता है । जी हाँ, जिस जगह हम अपने जीवन का अधिकांश, महत्वपूर्ण समय बिताते है अगर उसी में दोष है तो लाख चाह कर भी, बहुत प्रयास के बाद भी हमें अपने परिश्रम का श्रेष्ठ परिणाम मिलने में आशंका बनी रहती है ।

पहले समय में भवन की आयु न्यूनतम 100 वर्ष मानी जाती थी । भवन के स्वामी के पुत्र पौत्र आदि उसमे मिलकर लम्बे समय तक निवास करते थे , उस भवन के साथ लोगो की बहुत सी यादें जुडी होती थी और कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी संकट में क्यों ना हो वह उसको बेचने के बारे में सोचता भी नहीं था परन्तु यह बहुत ही खेद का विषय है कि आज वास्तु / ज्योतिष के अनुसार भवन की आयु घट कर लगभग 40 वर्ष ही रह गयी है । इन सबका एक प्रमुख कारण वास्तु के नियमो की पूर्णतया अवहेलना करना है । यदि हमारा भवन वास्तु के अनुरूप है तो वहाँ पर ना केवल परस्पर प्रेम, हर्ष, उल्लास और निरोगिता ही रहेगी वरन वहाँ रहती है । लेकिन वास्तु द्वारा इन्ही पंच तत्वों जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश के बीच की परस्पर क्रिया को ध्यान में रखकर इस प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए निश्चय ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किये जा सकते है ।



वास्तु विज्ञान भारत का अत्यंत प्राचीन ज्ञान है जिसकी हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अथक प्रयास से मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए रचना की है। वास्तु 'वस' शब्द से बना है जिसका अर्थ है वास करना । वास्तु का संस्कृत में अर्थ है मनुष्य एवं देवताओं का निवास स्थान । वास्तु केवल भवन निर्माण कला ही नहीं है वरन वास्तु में सम्पूर्ण देश, राज्य, नगर, भवन, हमारे बैठने ,सोने, खाना बनाने, भण्डारण, पूजा स्थल, स्नानघर आदि एवं निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सभी सामग्रियाँ आती है । इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वास्तु के सिद्धांतों का पालन करके बनाये गए निर्माणों में धन यश एवं मनवांछित सफलता की अल्प प्रयासों से ही प्राप्ति हो जाती है। भारतीय शास्त्रों में प्रत्येक छोटे बडे स्थान के देवता के रूप में वास्तुपुरुष को मान्यता दी गयी है । किसी भी भवन के निर्माण के समय वास्तु पुरुष की पूजा अनिवार्य मानी जाती है जिससे भवन के निवासियों को जीवन में सभी तरह के सुखों के साथ साथ धर्म, अर्थ,काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। प्रत्येक भवन में वास्तुपुरुष का अस्तित्वं माना जाता है । वास्तुपुरुष भवन में अपने हाथ पैरों को एक विशेष समय में मोडकर उलटे लेते रहते है । भवन में वास्तु पुरुष का सर ईशान कोण एवं उनके पैर नैत्रत्य कोण में माने जाते है।

वास्तु दोष :- अगर आपके भवन में रहने वाले लोग बार बार बीमार पडते है, उस भवन में रहने वालो के बीच आये दिन कलह रहती है, पर्याप्त मेहनत के बावजूद भी धन की कमी रहती है, अनावश्यक खर्चो का सामना करना पडता है, बनते हुए कार्यों में अडचने आ जाती है, संतान मनमाना कार्य करती है, भवन में रहने वाले तनाव में रहते है।

भवन में भय लगना है, रात में बुरे बुरे सपने आते है, भवन के आसपास या चमगादड नजर आते है तो आपके भवन में वास्तु दोष हो सकता है इसका तुरंत उपाय करें अन्यथा शायद जीवन भर पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ ना लगे ।

गजानन की जिहा देती है यह सीख

गजानन रूप में भी हम भगवान गणेश की वंदना करते हैं। गजानन अर्थात हाथी के मुख वाला। हाथी की जीभ अन्य प्राणियों से अनोखी होती है। गणेशजी के इस रूप में वाणी का महत्व प्रतिपादित होता है। मनुष्य की उत्तम वाणी महत्व को बढाती है और दोषपूर्ण वाणी सम्मान कम करती है। हाथी की जीभ तो बाहर निकलती ही नहीं। यह तो मुख के भीतरी भाग में है। अर्थात इससे वाणी के अनर्थ का भय नहीं है और संयम की सीख है। गजा का अर्थ उन ऋषियों और योगियों से भी जुडता है जो समाधि में बैठे रहते हैं और जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं। गणेश अपने इस रूप में हमें पदार्थगत वासना से उबरकर मोक्ष की राह तलाशने की सीख देते हैं। भगवान गणेश का यह रूप यह भी सीख देता है कि जिस तरह हाथी संयमित जीवन से 120 वर्ष जी सकता है मनुष्य भी नियंत्रण से लंबा और सुखी जीवन बिता सकता है।

इस तरह के उपाय से घर में हो रहे कलह-कलेश को दूर कर सुख-शांति पा सकते हैं



जीवन में सुख और शांति का बना रहना काफी मुश्किल होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी हो ऐसे में कुछ उपायों को अपनाकर शायद हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। शुक्ल पक्ष में पडने वाले किसी शुक्रवार के दिन पत्नी अपने हाथों से प्रेम पूर्वक साबूदाने की खीर बनाएं लेकिन उसमें शक्कर के स्थान पर मिश्री डालें। इस खीर को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और इसके बाद पति-पत्नी थोडी-थोडी एक-दूसरे को खिलाएं। भगवान से सुखमय दाम्पत्य की कामना करें। इस दिन किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र का दान करें। अपने शयनकक्ष में इत्र कदापि न रखें। कुछ दिनों तक यह प्रयोग करते रहें । कुछ ही दिनों में दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। बरगद(बड) के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर घर में रखें। घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा अथवा चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। उस पर सुबह दूर्वा अवश्य अर्पित करें।

धन संबंधी कार्य सोमवार एवं बुधवार को करें। नए कार्य, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार आदि शुभ कार्यों के लिए जाते समय घर की कोई महिला एक मुठ्ठी काले उडद उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर भूमि पर छोड दे तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। गरीब, असहाय, रोगी व किन्नरों की सहायता दान स्वरूप अवश्य करें। यदि संभव हो तो किन्नरों को दिए पैसे में से एक सिक्का वापस लेकर अपने कैश बॉक्स या लॉकर में रखें। इससे लाभ होगा। काली हल्दी की एक गांठ शुभ मुहूर्त में प्राप्त कर अपने घर में, व्यवसायी अपने कैश बॉक्स में तथा व्यापारी अपने गल्ले में रखें। रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बहेडे की जड या एक पत्ता तथा शंखपुष्पी की जड लाकर घर में रखें। चांदी की डिब्बी में रखें तो और भी शुभ रहेगा।

टोटके करते समय इनका ध्यान रखें-

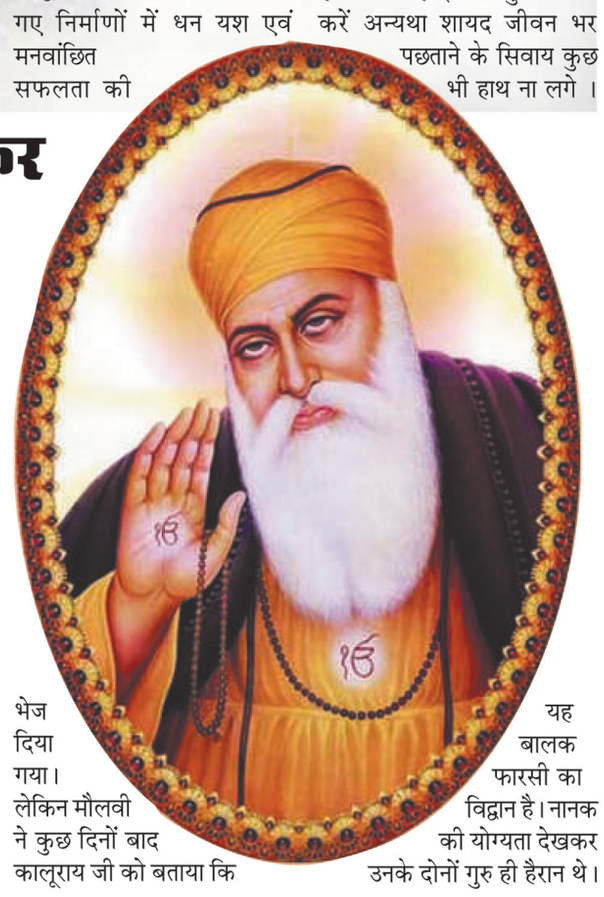
दिशा-निर्देश- सम्मोहन सिद्धि, देव कृपा प्राप्ति अथवा अन्य शुभ एवं सात्विक कार्यों की सिद्धि के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके टोटके किए जाते हैं। मान-सम्मान, प्रतिष्ठा व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले टोटकों के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ होता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके उन टोटकों को किया जाता है जिनका उदेश्य रोगों की चिकित्सा, मानसिक शांति एवं आरोग्य प्राप्ति होता है।

रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाले टोटकों के लिए मंगलवार एवं श्रावण मास उत्तम समय है। मां सरस्वती की प्रसन्नता व शिक्षा में सफलता के लिए बुधवार एवं गुरुवार तथा माघ, फाल्गुन और चैत्र मास में टोटका करना चाहिए। संतान और वैभव पाने के लिए गुरुवार तथा आश्विन, कार्तिक एवं मार्गशीर्ष मास में टोटकों का प्रयोग करना चाहिए।

नानक की योग्यता देखकर उनके गुरु भी थे हैरान

पंजाब का एक छोटा सा शहर तलवंडी में कालूराय बेदी की पत्नी तृप्ता देवी के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ। यह शिशु बालक था, जिसने बडे होकर अपना समूचा जीवन धार्मिक कट्टरता और धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों और अनाचारों का विनाश करने के लिए समर्पित कर दिया। कालूराय बेदी तलवंडी के शासक राय दुलार के प्रधान पटवारी थे। साथ ही अत्यधिक विश्वासपात्र भी। उनका घर धन-धान्य से भरा हुआ था। इसलिए शिशु का जन्मोत्सव बहुत धूम-धाम से मनाया गया। तृप्ता देवी ने पुत्री नानकी के जन्म के बाद एक पुत्र को जन्म दिया था। पुत्री का नाम नानकी इसलिए रखा गया क्यों कि उसका अधिक समय ननिहाल में ही गुजरा था। इसलिए बालक को बहिन के नाम का पर्याय देते हुए नानक के रूप में बुलाया जाने लगा।

बचपन से ही नानक में विलक्षण प्रतिभाएं देखने के मिलने लगीं थीं। वह किसी भी पेड के नीचे बैठकर 'सत करतार' का जप किया करते थे। पांच वर्ष की उम्र में ही उनकी पढाई शुरु हो गई। उनके पहले गुरु बने पंडित गोपाल के पास जाने लगे। वह इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि कुछ दिनों में ही पं.गोपाल मान गए कि वह जितने पढे लिखे हैं उससे कहीं अधिक ज्ञान नानक जी को है। इसके बाद नानक जी की फारसी शिक्षा शुरू हुई। उनको फारसी की शिक्षा देने के लिए मौलवी कुतबुद्दीन के पास भेज दिया गया। लेकिन मौलवी ने कुछ दिनों बाद कालूराय जी को बताया कि यह बालक फारसी का विद्वान है। नानक की योग्यता देखकर उनके दोनों गुरु ही हैरान थे।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सपा-बसपा की जड़ पर चोट देने की तैयारी में भाजपा

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ अलग-अलग जिलों का दौरा कर राजनीतिक माहौल बनाने में जुटे हैं तो बीजेपी की रणनीति सपा और बसपा के मजबूत माइक्रो सिस्टम पर चोट देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. बीजेपी ने जमीन स्तर संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ मैनेजमेंट शुरू किया है. बीजेपी ने गुरुवार को एक साथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है. इस बूथ सम्मेलन के जरिए जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने की नहीं बल्कि सपा-बसपा के वोटबैंक में सेंधमारी का भी प्लान बनाया है. उत्तर प्रदेश में आयोजित बूथ सम्मेलनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए।



राज्यसभा में खड़गे की कविता पर भड़के रिजिजू

नई दिल्ली। संसद के चालू मॉनसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गई. लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 फिर दो और बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12, फिर 2, फिर 3 और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित होने से पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कविता पढ़कर विरोध जाहिर किया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़क गए. दरअसल, शाम तीन बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही चौथी बार शुरू हुई, चेयर से उपसभापति हरिवंश ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बोलने को कहा. बोलने खड़े हुए खड़गे ने हाथों में एक पन्ना लिया हुआ था. उन्होंने कविता पढ़ना शुरू किया, सच को जिंदा रखने के लिए मर जाएंगे. ये दिल ये जान सब कुर्बान कर जाएंगे. मगर देश से अन्याय मिटाने के लिए हर चुनौती से टकरा जाएंगे।



नीट पर ठाकरे बंधु एक सुर में, छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा

मुंबई। नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों की पिटाई के मामले पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. दोनों नेताओं ने कहा कि छात्रों पर जो दबाव डाला जा रहा है और उन्हें जिस तरह पीटा जा रहा है, उसका असर पूरे देश में दिख रहा है. राज ठाकरे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अब मामला उनसे आगे बढ़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका है. वहीं उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में छात्रों से मुलाकात का अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह छात्राओं के कपड़े फाड़े गए और उन्हें कीलों वाली लाठियों से पीटा गया.दोनों नेताओं ने ऐलान किया है कि 26 तारीख, रविवार को मुंबई में शिवाजी पार्क से सिद्धिविनायक मंदिर तक एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा।



सिक्किम टनल हादसे में अब तक 25 शव बरामद

गंगटोक। सक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन एनएचपीसी तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में अब सभी 25 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. अधिकारियों के मुताबिक इस सुरंग में कुल 25 मजदूर फंसे थे. बचाव अभियान युद्धस्तर पर चल रहा है. देर रात करीब 10 बजे आसनसोल स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक दूसरी बचाव टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान में जुट गई. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और आसनसोल स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तेजी से बचाव एवं तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं. सोमवार 20 जुलाई को दोपहर तकरीबन 1 बजे यह हादसा हुआ था. अधिकारियों का कहना है कि शवों की पहचान के लिए जरूरत पड़ने पर छह्ह जांच भी कराई जाएगी. इस मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की है।



सोनम को फिर जाना होगा जेल, जमानत रद्द

इंदौर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने उसकी जमानत रद्द कर दी है और तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. इस फैसले के साथ ही बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.यह मामला उस समय देशभर में चर्चा का विषय बना था, जब शादी के कुछ समय बाद हनीमून पर गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या हो गई थी. मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. बाद में सोनम को जमानत मिलने के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि सोनम रघुवंशी को मिली जमानत उचित नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जमानत आदेश एक तकनीकी आधार पर मिला।



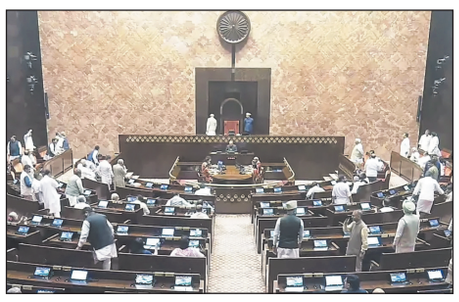
संसद में गतिरोध जारी, पांचवें दिन भी विधायी कामकाज ठप

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

नईदिल्ली। इस हफ़्ते के ट्रेंड को जारी रखते हुए, शुक्रवार को मॉनसून सत्र के पांचवें दिन संसद में बार-बार कार्यवाही स्थगित हुई और हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर पूरी चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और अब वे सोमवार सुबह 11 बजे फिर से मिलेंगे। वहीं, आज दोनों सदनों में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि वे नीट पेपर लीक मामले पर लोकसभा में बहस होने दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई भी बहाना देश में गलत संदेश देगा। हालांकि, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जोर देना जारी रखा। पिछले पांच दिनों में लोकसभा में कोई खासी विधायी कामकाज नहीं हो सका तथा प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सके। सदन की बैठक शुक्रवार सुबह शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। इसके बाद सदन ने कारगिल संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। समयऔर कैलेंडर

श्रद्धांजलि के बाद विपक्षी सदस्य नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में भी यह हंगामा जारी रहा जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।



राज्यसभा की कार्यवाही

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा करने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों और इसका विरोध कर रहे सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन अधिनियम) विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को वही वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है, जो वर्तमान में राष्ट्र गान 'जन गण मन को प्राप्त है।

हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि चार दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई विधायी कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन अधिनियम) विधेयक 2026 पेश करने को कहा। राय ने सदन में चर्चा करने और पारित करने के लिए यह विधेयक पेश किया। विपक्षी सदस्यों, विशेषकर वाम दलों के सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। हालांकि, ध्वनिमत से इस विधेयक को सदन में पेश कर दिया गया। इसके बाद उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन में सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ा टकराव

मेरे बोलने पर बंद हो जाता है माइक : राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को फिर से अपनी तीन मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार से सिर्फ तीन मांग हैं। शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। तभी हम संसद में बातचीत या चर्चा करेंगे।

उन्होंने आगे कहा 'प्रधानमंत्री प्रधान को बर्खास्त किए जाने से पहले हम कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना ही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के सदन में दिए गए बयान पर लोकसभा विपक्ष के सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'अभी मंत्री रिजिजू ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हमारे सांसदों से कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सामान्य प्रोटोकॉल के अनुसार, अगर कोई किसी दूसरे का नाम लेता है, तो उसे जवाब दिया जाता है। जब मैंने जवाब देना चाहा, तो मेरा माइक छीन लिया गया। मुझे मौका नहीं दिया गया।

तीन मांगें क्या हैं?

1) भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना होगा।

2) छात्रों पर हमला करने और उनकी पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

3) प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों से जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन से दूर रहने का आग्रह करने के बाद,विश्वविद्यालय की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पूछा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने वाले छात्रों को धमकाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई?



उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सोशल मीडिया पोस्ट को टैग करते हुए कहा, कृपया ध्यान दें, समय आने पर आप ही जवाबदेह होंगे। जिसमें छात्रों को जंतर मंतर से दूर रहने की सलाह दी गई थी। आप छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए धमकाने की हिम्मत कैसे करते हैं?

उनकी यह टिप्पणी गुरुवार रात दिल्ली विश्वविद्यालय के एक पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें कहा गया था, प्रिय छात्रों और शिक्षकों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए मायने रखती है। कृपया ध्यान दें कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कोई भी गैरकानूनी सभा या प्रदर्शन, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सख्ती से नियंत्रित है, कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।

सीजेपी प्रदर्शन पर आया आरएसएस के इंद्रेश कुमार का बयान

यह भारत की तरक्की के खिलाफ विदेशी ताकतों की साजिश

नईदिल्ली। सीनियर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के पीछे देश और विदेश की ताकतें हैं। उन्होंने दावा किया कि ये ताकतें भारत के विकसित, मज़बूत और शिक्षित देश बनने का विरोध करती हैं। नीट परीक्षा को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर बात करते हुए कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों ने शुरू में परीक्षा को लेकर चिंताएं जताई थीं, लेकिन बाद में वे भटक गए और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे।

कुमार ने मीडिया से कहा कि हालात ऐसे हैं कि देश में सकारात्मक राजनीति के दौर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों ने नीट का मुद्दा तो उठाया, लेकिन वे भटक गए और अपनी राजनीति करने लगे। उन्होंने भारत और दुनिया भर में मौजूद इन ताकतों पर देश के विकास के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वहाँ आने वाले युवाओं से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब तक एक बात तो साफ़ हो गई होगी- इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे देश और दुनिया की वे ताकतें हैं जो नहीं चाहतीं कि भारत एक विकसित, मज़बूत और शिक्षित देश बने। इसके बजाय, वे भारत को बर्बाद करना चाहती हैं।

कुमार ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल युवाओं से सकारात्मक मूल्यों को अपनाने और देश की तरक्की में रचनात्मक योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम के ज़रिए भारत के एक ग्लोबल रोल मॉडल के तौर पर उभरने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि आज, हज़ारों-लाखों स्टार्टअप्स के ज़रिए भारत पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर रहा है। इस रोल मॉडल को बनाने में हर किसी को सरकार का सहयोग करना चाहिए। अपनी भूमिका स्वतंत्र और सकारात्मक ढंग से निभाएँ ताकि आने वाली पीढ़ियाँ यह सीख सकें कि जब वैश्विक ताकतें भारत के विकास, शिक्षा, समृद्धि, खुशहाली, शांति और सद्भाव को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, तब ये वे लोग और युवा थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई।



आरएसएस नेता ने आगे कहा कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे बर्बाद तो न करें। अगर आप दूसरों को अच्छा करते हुए नहीं देख सकते, तो उसे खराब करने की कोशिश भी न करें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से यह भी कहा कि वे देश-निर्माण के काम में जुटने के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर, बनर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं से प्रेरणा लें।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज

हरारे। भारतीय टीम शनिवार को दूसरे टी-20 मुकाबले में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। जबकि हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले इस मैच में जिम्बाब्वे के लिए करो या मरो वाली स्थिति होगी। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली युवा भारतीय टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से शानदार जीत के साथ सीरीज पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक और जीत भारत को सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त दिला देगी, जबकि हार जिम्बाब्वे को एक और घरेलू सीरीज हार की ओर धकेल देगी।



भारत की शुरुआती जीत जबरदस्त बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी रही। युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़कर जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया, जबकि ईशान किशन (35) और कप्तान अय्यर (28 नाबाद) ने 40 गेंदें शेष रहते हुए 126 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। मेजबान टीम को अपने टॉप ऑर्डर से कहीं बेहतर प्रदर्शन की ज़रूरत होगी, जबकि तेज़ गेंदबाज़ ब्लेसिंग मुज़राबानी और रिचर्ड नगारवा को शुरुआती विकेट लेने होंगे ताकि भारत के आक्रामक बल्लेबाजों को एक बार फिर मैच पर हावी होने से रोका जा सके।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर बल्ले और गेंद के बीच बराबरी का मुकाबला होने की उम्मीद है और मैच के दौरान मौसम भी साफ रहने का अनुमान है। हालांकि इस मैदान पर आम तौर पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को फायदा मिलता रहा है, लेकिन पहले मैच में भारत की आसान जीत से पता चला कि पिच पूरे समय स्ट्रोक-प्ले के लिए अच्छी रहती है। अपनी मजबूत स्थिति के कारण, भारत इस मैच में सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार के तौर पर उतरेगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स धड़ाम, निफ्टी 23,800 के नीचे फिसला

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुए, जो जनवरी के पहले सप्ताह के बाद सबसे लंबी गिरावट का दौर है। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों, महंगाई और आर्थिक वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंताओं का असर बाजार की धारणा पर देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 332 अंक यानी 0.43 फीसदी गिरकर 76,059.77 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 102.15 अंक यानी 0.43 फीसदी टूटकर 23,767.45 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में Eternal, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा (रूरू) सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयर रहे। व्यापक बाजार में भी दबाव देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.10 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.32 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए।

कच्चा तेल 90 डॉलर के पार रहा तो महंगा होगा पेट्रोल

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी का असर अब घरेलू ईंधन बाजार पर भी पड़ सकता है। सरकारी तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संकेत दिया है कि यदि कच्चा तेल लंबे समय तक 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहता है, तो पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन करना पड़ सकता है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल बाजार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और अंतिम फैसला वैश्विक कीमतों की दिशा पर निर्भर करेगा। बीपीसीएल के निदेशक वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने कहा कि हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। कंपनी का मानना है कि यदि यह तेजी अस्थायी साबित होती है तो कीमतों में बदलाव की जरूरत नहीं होगी लेकिन लंबे समय तक ऊंचे स्तर बने रहने पर लागत का दबाव बढ़ेगा।

29 जुलाई को खुलेगा 9,275 करोड़ रुपए का आईपीओ

नईदिल्ली। देश की प्रमुख हॉस्पिटल चैन में शामिल मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 9,275 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 29 जुलाई को निवेशकों के लिए खुलेगा। कंपनी यह राशि फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाएगी। कंपनी ने आईपीओ के लिए 560-590 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। ऊपरी मूल्य बैंड पर कंपनी का मूल्यांकन 77,600 करोड़ रुपए से अधिक बैठता है। बेंगलूरु स्थित कंपनी के आईपीओ में 8,000 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि मौजूदा शेयरधारक 2.16 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचेंगे। कंपनी आईपीओ से प्राप्त धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से कर्ज चुकाने और अधिग्रहण के लिए करेगी। तीन दिन तक खुला रहने वाला यह आईपीओ 31 को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली 28 जुलाई को खुलेगी।

जुलाई में प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ धीमी

नईदिल्ली। भारत के निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में जुलाई महीने के दौरान सुस्ती देखने को मिली है। एचएसबीसी फ्लेश इंडिया पीएमआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पिछले तीन साल से अधिक समय के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह संकेत देता है कि कंपनियों के कामकाज की रफ्तार अब पहले के मुकाबले धीमी पड़ रही है, भले ही विस्तार अभी भी जारी है। जून में जहां पीएमआई 57.1 था, वहीं जुलाई में यह घटकर 54.3 पर आ गया, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे कमजोर स्तर है। रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार की मौजूदा परिस्थितियां कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ऑर्डर का कैंसिल होना और ग्राहकों की ओर से कम पूछताछ जैसे कारणों ने नई मांग को प्रभावित किया है।

क्या 16वें वित्त आयोग ने राजकोषीय संघवाद का संतुलन केंद्र की ओर झुका दिया है?

एम गोविंद राव

संघीय व्यवस्था में केंद्र से राज्यों को होने वाले राजकोषीय अंतरण के चार महत्त्वपूर्ण आर्थिक कारण होते हैं। पहला, 'तुलनात्मक लाभ' के सिद्धांत के अनुसार, काम के बंटवारे और राजस्व के स्रोतों के बीच तालमेल न होने से असंतुलन ऊपर से नीचे तक दिखने लगता है। राज्यों पर बिना फंड वाले काम का बोझ न पड़े, इसके लिए इस असंतुलन को ठीक करने की जरूरत है।

दूसरा कारण, देश में 'बराबर वालों के साथ बराबरी का व्यवहार' करने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्य कर संग्रह की समान क्षमता के साथ समान स्तर की सार्वजनिक सेवाएं दे सकें। इसके लिए राजस्व और लागत से जुड़ी कमियां पूरी करने के लिए अंतरण की आवश्यकता होती है।

तीसरा, जब सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में 'स्पिलओवर' (एक क्षेत्र में सेवा का लाभ दूसरे क्षेत्र को भी मिलना) की स्थिति हो, तो सेवाओं की अपर्याप्त आपूर्ति से बचने के लिए राज्यों को समान शर्तों के साथ अनुदान देकर सब्सिडी देना जरूरी हो जाता है।

आखिर में, केंद्र सरकार अनुदान देकर राज्यों की सेवाओं का इस्तेमाल अपनी तय जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए एक एजेंसी के तौर पर कर सकती है। ऊर्ध्वाधर (केंद्र और राज्य के बीच) और क्षैतिज (राज्यों के बीच) असंतुलन ठीक करने के लिए दी जाने वाली रकम आम तौर पर कर के बंटवारे या शर्त रहित अनुदान के रूप में होती है, जबकि स्पिलओवर' प्रभाव दुरस्त करने के लिए आवंटन रकम समान शर्तों के साथ सशर्त होती है। एजेंसी के काम करने के लिए हस्तांतरण लागत की भरपाई के तौर पर सशर्त होता है।

संविधान केंद्र और राज्यों की वित्तीय



क्षमता एवं जरूरतों में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी वित्त आयोग को सौंपता है। हर पांच साल में नियुक्त होने वाले इस आयोग का कार्य अन्य बातों सहित केंद्र एवं राज्यों के बीच और राज्यों के आपस में कर विभाजन के साथ ही राज्यों को राजस्व के लिए सहायता अनुदान देने की सिफारिश करना है।

आयोग आने वाले पांच साल के लिए केंद्र और राज्यों की अनुमानित वित्तीय क्षमता और जरूरतों के आधार पर सिफारिशें करता है। इसके बाद कर बंटवारे योग्य कोष में केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के आपस में हिस्से तय किए जाते हैं। इस कोष में कर संग्रह की लागत घटाने और उपकर एवं अधिभार से होने वाली कमाई हटाने के बाद बची हुई केंद्रीय कर की रकम शामिल होती है।

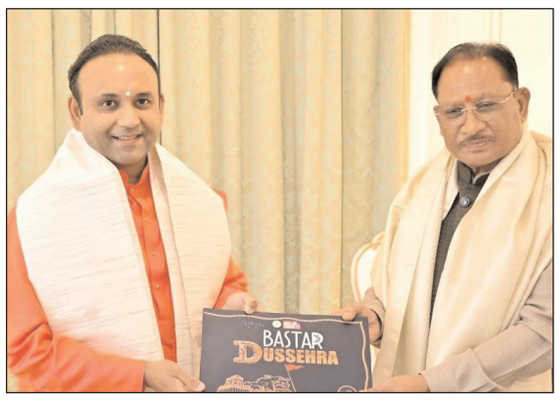
राज्यों का हिस्सा तय करते समय आयोग मुख्य रूप से राजस्व और लागत से जुड़ी कमियों और खर्च की आवश्यकता दिखाने वाले पैमाने पर विचार करता है।

इस कार्य में निर्णय लेना जरूरी हो जाता है और जैसा चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीवी राजमन्नार ने कहा था, 'आयोग की सिफारिशें पांच लोगों या उनमें से ज्यादातर लोगों की निजी राय पर आधारित एक जुआ' होती हैं। फिर भी ये फैसले लेते समय उनसे उम्मीद की जाती है कि वे (1) सातवीं अनुसूची में बताए गए विभाजन के तरीके (2) व्यापक आर्थिक स्थिरता और केंद्र व राज्यों की विकास संबंधी जरूरतों और (3) कामकाज के क्षेत्रों में स्पष्टता का पालन करें। एक मध्यस्थ और अर्द्ध ङ्कन्यायिक विशेषज्ञ संस्था के तौर पर आयोग से निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है।'

शुरू में केवल व्यक्तिगत आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से होने वाली कमाई ही बांटी जा सकती थी। दसवें वित्त आयोग की सिफारिश पर संविधान के 80 वें संशोधन ने सभी केंद्रीय करों को विभाज्य निधि में शामिल कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि छठे वित्त आयोग तक बंटवारे का फॉर्मूला मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच असंतुलन पर केंद्रित था और जाहिर है, राज्यों के बीच हिस्सेदारी मुख्य रूप से आबादी के आधार पर तय की जाती थी जिसमें व्यक्तिगत आयकर संग्रह को थोड़ा महत्त्व (10-20 फीसदी) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी को लगभग 10 फीसदी तवज्जो दी जाती है।

सत्य साई ग्राम स्वर्ण जयंती समारोह

भारत की शिक्षा परंपरा सदैव मूल्य-आधारित : सीएम साय



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बेंगलुरु के मुद्देनहल्ली में सत्य साई ग्राम स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। साय ने कहा कि मैं सद्गुरु श्री मधुसूदन साई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे सत्य साईं ग्राम के इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है कि मुझे इस संस्थान की पचास वर्षों की प्रेरणादायी यात्रा का साक्षी बनने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि सदगुरु श्री मधुसूदन साई का जन्म छत्तीसगढ़ की पावन धरती बिलासपुर में हुआ। हम सभी के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारे राज्य की इस पवित्र भूमि ने ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष को जन्म दिया, जिनका जीवन आज संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बन चुका है। सदगुरु श्री मधुसूदन साई जी की यह अद्भुत यात्रा भी केवल अपने गुरु भगवान सत्य साई बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आरंभ हुई। यही गुरु-शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है।

सीएम साय ने कहा, यह प्रसन्नता का विषय है कि इस स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत 'मूल्य शिक्षा' पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से हुई। आज के युग में, जब तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, तब चरित्र निर्माण और मूल्यों पर आधारित शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भारत की शिक्षा परंपरा सदैव मूल्य-आधारित रही है। तक्षशिला, नालंदा और गुरुकुल परंपरा ने ज्ञान के साथ चरित्र, अनुशासन, सेवा और करुणा का संस्कार दिया। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

साय ने कहा, आज का युग एआई, डिजिटल क्रांति और तीव्र तकनीकी परिवर्तन का युग है। तकनीक हमारे जीवन को सरल बना रही है, लेकिन यदि उसके साथ नैतिकता, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्य नहीं होंगे, तो प्रगति अधूरी रह जाएगी। विकसित भारत का सपना मूल्य-आधारित शिक्षा के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमें ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो तकनीक में दक्ष होने के साथ-साथ संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी हों। सत्य साईं संस्थान जैसे संस्थानों का योगदान इस दिशा में अत्यंत प्रेरणादायक है। इस संस्थान ने वर्षों से शिक्षा को सेवा, चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्यों से जोड़कर समाज के सामने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कहा, सदगुरु श्री मधुसूदन साई जी ने कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय स्थापित किए, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पूर्णत: नि:शुल्क एवं मूल्य-आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। आज लगभग 4,000 विद्यार्थी, कक्षा 6 से लेकर पीएचडी तक, पूर्णत: नि:शुल्क शिक्षा, आवास, भोजन तथा समग्र व्यक्तित्व विकास प्राप्त कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के विकास, कौशल शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सत्य साईं ग्राम जैसी संस्थाओं से प्रेरणा लेकर हम अपने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ कर सकेंगे।सीएम ने कहा, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे संस्कार, सेवा, कौशल और चरित्र निर्माण से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति भी इन्हीं उद्देश्यों पर बल देती है और सत्य साईं ग्राम इस सोच का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मेरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से निकले विचार शिक्षा को अधिक मानवीय, समावेशी और मूल्य-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। पचास वर्ष पहले दूरदर्शी शिक्षाविद् श्री मडियाला नारायण भट्ट जी ने सत्य साईं ग्राम रूपी जिस बीज को यहाँ बोया था, वह श्री सत्य साईं बाबा के आशीर्वाद से आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में पल्लवित हो गया है।

वन मंत्री की पहल पर शुरू हुआ जिले का पहला 'ट्री एटीएम'



रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए श्मोबाइल ट्री एटीएमश् की अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके मुख्य उद्देश्य है सुकमा, बस्तर और जशपुर जिलों में शुरुआत, घर-घर जाकर नि:शुल्क फलदार व औषधीय पौधे वितरण, और श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान को जनआंदोलन बनाना है .

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप की पहल और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के प्रयासों के तहत बीजापुर जिले में अभिनव पहल की गई है। जिले में पहली बार 'ट्री एटीएम' शुरू किया गया है। इसके साथ ही डीएवी स्कूल में सीडबॉल निर्माण प्रशिक्षण और वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वनमंडल बीजापुर के बीजापुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एनएच-63 मुख्य मार्ग पर जिला अस्पताल चौक, एसपी बंगले के पास जिले का पहला 'ट्री एटीएम' स्थापित किया गया है। इसका शुभारंभ जिला पंचायत के श्री मैथ्यूज कुजूर ने किया।

इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों और ग्रामीणों को एक ही स्थान पर आसानी से नि:शुल्क पौधे उपलब्ध कराना है।अब लोगों को पौधों के लिए अलग-अलग स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने नि:शुल्क पौधा वितरण वैन को दिखाई हरी झंडी



रायपुर। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ प्रवास के दौरान आज अपने निवास कार्यालय से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वनमंडल रायगढ़ द्वारा संचालित नि:शुल्क पौधा वितरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभिनव पहल के माध्यम से रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नागरिक अब केवल एक फोन कॉल पर अपने घर तक नि:शुल्क पौधे प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री के श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्रीओपी चौधरी ने कहा कि वन विभाग की यह पहल नागरिकों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। अब यदि कोई व्यक्ति अपने घर, आंगन, बाड़ी, खेत, बगीचे, तालाब किनारे अथवा अन्य उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण करना चाहता है, तो उसे केवल टोल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद वन विभाग की टीम सीधे उसके घर पहुंचकर नि:शुल्क पौधे उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से लोगों को पौधों के लिए नर्सरी या विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अधिक से अधिक लोग पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान से जुड़ सकेंगे।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान प्रकृति के प्रति सम्मान और मातृऋण के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे, तो आने वाले समय में रायगढ़ हरियाली की नई पहचान बन सकता है। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार आम, अमरूद, नींबू सहित विभिन्न फलदार पौधों के साथ-साथ छायादार एवं अन्य उपयोगी प्रजातियों के पौधे भी प्राप्त कर सकेंगे। गुणवत्तापूर्ण पौधों की सहज उपलब्धता से पौधारोपण

कांग्रेस के रवैये ने माहौल को बिगाड़ा: अरुण साव



रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाने में पिछले 18 घंटे से जारी कांग्रेस नेताओं का धरना पुलिस प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद आखिरकार खत्म हो गया है। पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर मामले से जुड़े भाजपा नेताओं पर स्नढ्ढक्र दर्ज करने और दर्ज मामलों की निष्पक्ष समीक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद राज्य में बयानों की तीखी तीरंदाजी शुरू हो गई है। डिप्टी ष्टरूअरुण साव ने कांग्रेस के इस रवैये और थाने में दिए गए धरने पर बड़ा हमला बोला है।अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण था, लेकिन कांग्रेस के रवैये ने माहौल को बिगाड़ा।उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण तरीके से घेराव कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कांग्रेस के लोगों ने जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम किया। उकसाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने लाठियां लहराईं और अपने झंडे लहराए।इसके बाद भी जब मामला बढ़ा, तो कांग्रेस के नेता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को खुलेआम धमकियां दे रहे थे कि सरकारें आती-जाती हैं, हम देख लेंगे। अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को अनावश्यक रूप से तूल देकर विषय बनाने की कोशिश कर रही है।

रायपुर में यातायात पुलिस और नगर निगम का बड़ा अभियान



रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारु, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पचपेड़ी नाका, पुजारी पार्क क्षेत्र और पंडरी स्थित कपड़ा मार्केट मंडी गेट के आसपास सड़क एवं फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के बाद इन क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुगम हुई और वाहन चालकों व आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली।

डीसीपी यातायात श्रीमती अर्चना झा के निर्देशानुसार पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की यातायात शाखा और नगर निगम की संयुक्त टीम ने यह अभियान संचालित किया। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क किनारे किए जा रहे अतिक्रमण के कारण वाहन चालकों एवं पैदल यात्रियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक मार्गों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, गुमटियां और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा सड़क तक सामान फैलाकर रखा गया था, जिससे आने-जाने वाले वाहनों को परेशानी हो रही थी। टीम ने ऐसे दुकानदारों को तत्काल सामान हटाने के निर्देश दिए और मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया।पचपेड़ी नाका और पुजारी पार्क क्षेत्र शहर के व्यस्त इलाकों में शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। वहीं पंडरी कपड़ा मार्केट मंडी गेट क्षेत्र में भी व्यापारिक गतिविधियों के कारण अक्सर भीड़ और यातायात दबाव की स्थिति बनती है। सड़क किनारे अतिक्रमण होने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होती थी और कई बार जाम की स्थिति भी निर्मित हो जाती थी। संयुक्त अभियान के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों और अतिक्रमण करने वाले लोगों को समझाइश दी कि सड़क और फुटपाथ आम जनता के उपयोग के लिए होते हैं। इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा करने से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। अधिकारियों ने सभी संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी ।यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

अतिथि शिक्षकों की हड़ताल खत्म, आश्वासन के बाद लिया फैसला



रायपुर। 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने आखिरकार अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है। हालांकि अतिथि शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 5 सितंबर 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे एक बार फिर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। दुर्ग में प्रेसवार्ता कर अतिथि शिक्षक संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। शिक्षकों ने कहा कि वे आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2016 से मिल रहा मानदेय आज की महंगाई के दौर में उनके लिए बेहद कम है। उनका कहना है कि कई शिक्षक 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर और नक्सल प्रभावित इलाकों में जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचते हैं। अतिथि शिक्षकों का दावा है कि उनके प्रयासों से दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित



रायपुर। बच्चों की असाधारण प्रतिभा, नवाचार, साहस और सामाजिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सर्वोच्च बाल सम्मान माना जाता है, जो उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।विभागीय जानकारी के अनुसार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अभिभावक, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं और अन्य व्यक्ति भी योग्य बच्चों का नामांकन कर सकते हैं। सभी आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

विश्व स्तनपान सप्ताह के पहले यूनिसेफ की कार्यशाला



रायपुर। मातृ एवं शिशु पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए यूनिसेफ ने रायपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह एवं स्वस्थ आहार विषय पर आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। होटल सयाजी में आयोजित इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया तथा स्तनपान, स्वस्थ आहार और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने पर चर्चा की। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए अनिल गुलाटी, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ ने कहा कि मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी वाहक है। तथ्यपरक और वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित रिपोर्टिंग भ्रांतियों को दूर करने के साथ-साथ परिवारों को ऐसे व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे प्रत्येक बच्चे को जीवन की स्वस्थ शुरुआत मिल सके।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने वन महोत्सव का किया शुभारंभ

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान 3.0 का शुभारंभ लोरमी विकासखण्ड के ग्राम बैगाकापा में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने 'वृक्ष मित्र वाहन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन गॉवों-शहरों में जाकर नीबू, मुनगा, बिही, जामुन आदि के पौधे वितरित कर नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करेगी।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक चुनौती है और इससे निपटने के लिए वृक्षारोपण के साथ वर्षा जल का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति के संतुलन के लिए पेड़, पानी और पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रेरित किया, ताकि ग्रीष्मकाल में जल संकट से बचा जा सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कलेक्टर कुन्दन कुमार, वनमंडलाधिकारी अभिनव कुमार, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय और जिला पंचायत के सीईओ गोकुल रावटे के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामीणजन और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

मानसून और बारिश से बढ़ीं मौसमी बीमारियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत के साथ लगातार हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. इसके बाद अब मौसमी और संक्रमण से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं. रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में सामान्य दिनों की तुलना में ओपीडी में मरीजों की संख्या करीब 50 फीसदी बढ़ गई है.

मेकाहारा के एमडी मेडिसिन डॉ. योगेंद्र मल्होत्रा के अनुसार, बारिश के मौसम में जलभराव और गंदे पानी की वजह से संक्रमण तेजी से फैलता है. इस दौरान वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीलिया और दस्त जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मेकाहारा के एमडी मेडिसिन डॉ योगेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि बारिश के इस मौसम में जल जमाव या पानी भरने की वजह से इंफेक्शन फैलता है जिसके कारण बीमारी और वेक्टर जनित बीमारियां ज्यादा होती हैं. ऐसी स्थिति में लोगों को पीलिया, मलेरिया, सर्दी खांसी, बुखार, हाथ पैर के साथ ही पूरे शरीर में दर्द होना. इस तरह के मरीजों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ गई है. सामान्य दिनों की तुलना में ओपीडी में 50त्न मरीज की संख्या बढ़ी है. मुख्य तौर पर मरीजों में बुखार, हाथ पैर में ज्यादा दर्द होना, उल्टी दस्त, पीलिया, ठंड के साथ बुखार आना, पेट में दर्द होना इस तरह के लक्षण वाले मरीज आते हैं।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की टीम और इंफ्लुएंसर्स की सार्थक चर्चा



रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड लगातार नवाचारपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में कांकेर के ऐतिहासिक कांकेर पैलेस में आज छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की टीम तथा राज्य के विभिन्न जिलों से आए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स (इंफ्लुएंसर्स) ने कांकेर पैलेस के युवराज जयप्रताप से सौजन्य भेंट की। यह मुलाकात प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म को नई दिशा देने, कांकेर की ऐतिहासिक धरोहरों को व्यापक पहचान दिलाने तथा बस्तर अंचल की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही।

भेंट के दौरान युवराज जयप्रताप ने कांकेर रियासत के गौरवशाली इतिहास, राजमहल की स्थापत्य कला, स्थानीय संस्कृति तथा क्षेत्र की विशिष्ट परंपराओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कांकेर केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के कारण भी पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षक गंतव्य है। उन्होंने कहा कि विरासत स्थलों का संरक्षण और उनका प्रभावी प्रचार-प्रसार पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है।

बैठक में विशेष रूप से कांकेर और आसपास के ऐसे कम चर्चित पर्यटन स्थलों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वे व्यापक स्तर पर पर्यटकों की पहुंच से दूर हैं। इन स्थलों को डिजिटल माध्यमों के जरिए देश-विदेश के यात्रियों तक पहुंचाने, उनकी विशिष्टताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने तथा उन्हें पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अनेक सुझाव सामने आए। यह भी विचार किया गया कि प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और विरासत पर्यटन को एकीकृत रूप से विकसित कर कांकेर को एक बहुआयामी पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। बैठक के दौरान हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पर्यटन आधारित रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। युवराज जयप्रताप ने भी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाने का यह प्रयास निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगा।

सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू, 21 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव के आधार पर सहायक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है, जो 21 अगस्त 2026 तक चलेगी।

जारी अधिसूचना के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज करना होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। हालांकि परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर ष्टत्रश्वस्क्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं को देखते रहें।भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अभ्यर्थियों की संख्या और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र का चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। भुगतान के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य उपलब्ध डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क भुगतान करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.